दिसम्बर 1, 2024

मूल्य 30 रुपये

अंक 1

JAGRUK PLUS

BREAKING NEWS

ब्रांड पायलट..

प्रदेश को कर्जे में फंसा गए गहलोत

दरक गया केजरीवाल का किला

जादूगर कौन...

सीएम भजनलाल या गहलोत

राइजिंग राजस्थान

में निवेश का रिकॉर्ड

JAGRUK PLUS
BREAKING NEWS

भाजपा ही क्यों?

देश में साल दर साल हुए चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसा क्यों है कि मतदाता भाजपा के उपर ही मुहर लगा रहा है?

इसकी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रवाद के साथ विकास की धार है। भाजपा राष्ट्रवाद और धर्म की बात करती है। सत्ता में रहते हुए विकास के काम करती है। सत्ता की चाबी मिलने पर योग्य लोगों को मुखिया बनाती है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के दवाब के सामने झुकने के बजाए असल हकदार नेताओं को आगे बढ़ाती है।

दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल जाति की बात करते हैं। जाति-धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। अगर सत्ता मिल जाए तो विकास के बजाए निजी हित आगे रखते हैं। ऐसे लोगों को मुखिया बनाया जाता है जो कि बूढ़े क्षत्रप हैं।

इसी वजह से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में भाजपा लगातार सबसे बड़ा दल बनकर विधानसभा में पहुंची है। राजस्थान और यूपी के उपचुनावों में अधिकांश सीटों पर भाजपा जीती है।

प्रधान संपादक- नीरज शर्मा
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर- रामहंस शर्मा
एडिटर- राघवेंद्र तिवारी
डिप्टी एडिटर- गौरव राय

संपादकीय कार्यालय- 41, आरआर शोपिंग सेंटर, कोकावास, टोंक रोड़ (जयपुर)
ग्राहक सेवा नंबर - मो. 8306944609
रजिस्टर्ड कार्यालय- FM-201, प्लॉट नंबर-50A, अरावली हिल्स जगतपुरा, जयपुर।
सभी विवादों का निपटारा जयपुर और राजस्थान की सीमा में आने वाली अदालतों/फोरमों में किया जाएगा।

जागरूक प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नीरज शर्मा निवासी सिकरोरी, तह. कुम्हेर, जिला भरतपुर।

RNI- RAJHIN/2016/67664

एक नजर

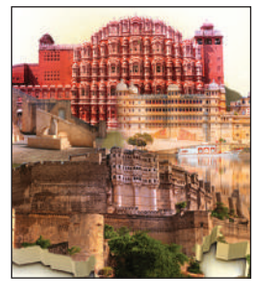

2 कवर स्टोरी
दस लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में भजनलाल सरकार

6 कांग्रेसमैन
ब्रांड पायलट...

8 राजनीति के सौदागर
गहलोत सरकार ने किया था राजस्थान में रामबाग के चूहों जैसा काम

11 महत्वाकांक्षी मजबूरी
केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब के सीएम! भगवंत मान को हटाने की रची साजिश

14 ऐतिहासिक जीत
कांग्रेस के मोदी विरोधी एजेंडे की खुल गई पोल, किसान नेता की जमानत जब्त

18 ढहता किला
राजस्थान के बाद हरियाणा को भी ले डूबे अशोक गहलोत

22 कार्रवाई का कमाल
साइबर ठगी का गढ़ मेवात, सरकार और नेता बदलते ही कैसे बिखरने लगा?

26 अपराधमुक्त राज्य
भजनलाल सरकार के 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' ने तोड़ी राजस्थान में गौ तस्करों की कमर

35 काला चिट्ठा
प्रदेश को कर्जे के दलदल में फंसा गए अशोक गहलोत। जानिए कर्ज लेकर घी पीने का एक-एक किस्सा

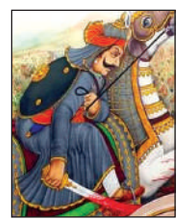

30 ऐतिहासिक कदम
महाराणा प्रताप को पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय गौरवशाली इतिहास का युगांतकारी कदम

39 विकसित प्रदेश
राजस्थान की तस्वीर बदल देंगी भजनलाल सरकार की 10 योजनाएं

43 रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन
जादूगर कौन...? सीएम भजनलाल या गहलोत

46 राजस्थान अपडेट

JAGRUK PLUS
BREAKING NEWS

भाजपा ही क्यों?

देश में साल दर साल हुए चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसा क्यों है कि मतदाता भाजपा के उपर ही मुहर लगा रहा है?

इसकी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रवाद के साथ विकास की धार है। भाजपा राष्ट्रवाद और धर्म की बात करती है। सत्ता में रहते हुए विकास के काम करती है। सत्ता की चाबी मिलने पर योग्य लोगों को मुखिया बनाती है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के दवाब के सामने झुकने के बजाए असल हकदार नेताओं को आगे बढ़ाती है।

दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल जाति की बात करते हैं। जाति-धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। अगर सत्ता मिल जाए तो विकास के बजाए निजी हित आगे रखते हैं। ऐसे लोगों को मुखिया बनाया जाता है जो कि बूढ़े क्षत्रप हैं।

इसी वजह से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में भाजपा लगातार सबसे बड़ा दल बनकर विधानसभा में पहुंची है। राजस्थान और यूपी के उपचुनावों में अधिकांश सीटों पर भाजपा जीती है।

प्रधान संपादक- नीरज शर्मा
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर- रामहंस शर्मा
एडिटर- राघवेंद्र तिवारी
डिप्टी एडिटर- गौरव राय

संपादकीय कार्यालय- 41, आरआर शोपिंग सेंटर, कोकावास, टोंक रोड़ (जयपुर)
ग्राहक सेवा नंबर - मो. 8306944609
रजिस्टर्ड कार्यालय- FM-201, प्लॉट नंबर-50A, अरावली हिल्स जगतपुरा, जयपुर। सभी विवादों का निपटारा जयपुर और राजस्थान की सीमा में आने वाली अदालतों/फोरमों में किया जाएगा।

जागरूक प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नीरज शर्मा निवासी सिकरोरी, तह. कुम्हेर, जिला भरतपुर से प्रकाशित और भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, जयपुर (राजस्थान) से मुद्रित।

RNI- RAJHIN/2016/67664

एक नजर

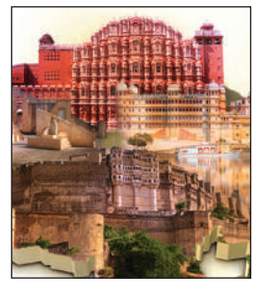

2 कवर स्टोरी
दस लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में भजनलाल सरकार

6 कांग्रेसमैन
ब्रांड पायलट...

8 राजनीति के सौदागर
गहलोत सरकार ने किया था राजस्थान में रामबाग के चूहों जैसा काम

11 महत्वाकांक्षी मजबूरी
केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब के सीएम! भगवंत मान को हटाने की रची साजिश

14 ऐतिहासिक जीत
कांग्रेस के मोदी विरोधी एजेंडे की खुल गई पोल, किसान नेता की जमानत जब्त

18 ढहता किला
राजस्थान के बाद हरियाणा को भी ले डूबे अशोक गहलोत

22 कार्रवाई का कमाल
साइबर ठगी का गढ़ मेवात, सरकार और नेता बदलते ही कैसे बिखरने लगा?

26 अपराधमुक्त राज्य
भजनलाल सरकार के 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' ने तोड़ी राजस्थान में गौ तस्करों की कमर

35 काला चिट्ठा
प्रदेश को कर्जे के दलदल में फंसा गए अशोक गहलोत। जानिए कर्ज लेकर घी पीने का एक-एक किस्सा

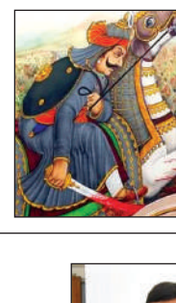

30 ऐतिहासिक कदम
महाराणा प्रताप को पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय गौरवशाली इतिहास का युगांतकारी कदम

39 विकसित प्रदेश
राजस्थान की तस्वीर बदल देंगी भजनलाल सरकार की 10 योजनाएं

43 रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन
जादूगर कौन...? सीएम भजनलाल या गहलोत

46 राजस्थान अपडेट

राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश का बनेगा रिकॉर्ड

10 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में भजनलाल सरकार

अब तक 27 लाख करोड़ के एमओयू हो गए हैं, जिनमें से 19.39 लाख करोड़ रुपये के एमओयू अकेले एनर्जी सेक्टर में हुए हैं।

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

राजस्थान में जल्द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आगाज होने वाला है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से पहले ही प्रदेश पर कुबेर की बारिश हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निवेश के संबंध में किए गए एमओयू ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस समिट में पहली पर 25 देशों की भागीदारी होगी। इनमें जापान, डेनमार्क, मलेशिया, स्पेन, द. कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्यूबा, इजिप्ट, फिनलैंड, यूएसए, जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड, नामीबिया, यूएई, पोलैंड, कतर, रूस, सिंगापुर, मोरक्को, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, नेपाल शामिल है। ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट में इन देशों के मंत्री, राजदूत और बड़े व्यापारिक संगठन शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर अब तक 27 लाख करोड़ के एमओयू हो गए हैं। इनमें से 19.39 लाख करोड़ रुपये के एमओयू अकेले एनर्जी सेक्टर में हुए हैं। इस

समिट से राज्य के सभी हिस्सों में बड़ा निवेश होगा और युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान हो जाएगी।

राइजिंग राजस्थान समिट- 2024 का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक होगा। इससे पहली बार प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवाओं को अपने जिलों में ही आसानी से रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि पांच लाख से अधिक नौकरियां निजी क्षेत्र में युवाओं को दी जाएंगी। इसके अलावा पांच साल के भीतर कुल पांच लाख सरकारी नौकरियां भजनलाल सरकार देगी। इस तरह से पांच साल के भीतर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इससे काफी हद तक युवाओं को घर से दूर दूसरे राज्यों में नौकरियों के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान

राजस्थान के लिए बिजली उत्पादन हमेशा से चुनौती रहा है। गहलोत सरकार के समय पर उर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। प्रदेश की इस कमजोरी को ही भजनलाल सरकार ने अपनी ताकत बनाने का फैसला किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट में सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी के क्षेत्र में किया जा रहा है। इस समिट के जरिए राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सरल बनाया जा रहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशक राजस्थान आएं और उनको निवेश करने में किसी तरह की परेशानी न हो। राजस्थान को सोलर एनर्जी का हब बनाने की तैयारी है। प्री-समिट में ऊर्जा

जानें क्या है 'राइजिंग राजस्थान'

'राइजिंग राजस्थान' राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना है। इस तरह की पहल की शुरुआत संभवत सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 'बाइब्रेंट गुजरात' कार्यक्रम के जरिये हुई थी। की थी। इस कार्यक्रम की सफलता के दम पर अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही महाराष्ट्र को पछाड़कर गुजरात को देश का नंबर एक जीडीपी वाला प्रदेश बना। इसके बाद देश के अलग-अलग राज्यों में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ। राइजिंग राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जीडीपी को 2028 तक दोगुने से भी अधिक करने का लक्ष्य तय किया है। इसको हासिल करने के लिए देश-विदेश की बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी कर राजस्थान के विभिन्न सेक्टरों में भारी मात्रा में निवेश को आमंत्रित किया गया है। इससे राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही लाखों नए रोजगार का सृजन होगा। जिसके माध्यम से ही राज्यों के उदय के साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी पाया जा सकेगा।

कैसे काम करेगा 'राइजिंग राजस्थान'

तीन दिवसीय 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2024' में देश-विदेश के प्रतिनिधि और उद्यमी शामिल होंगे। भजनलाल सरकार की ओर से किए गए 27 लाख करोड़ के एमओयू के आधार पर निवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में जिलों के आधार पर निवेश करने की चरणबद्ध प्रक्रिया तय की जाएगी। नई कंपनियां निवेश का पूरा खाका सरकार के सामने पेश करेंगी। इसी से तय होगा कि कौन-कौन सी कंपनियां किन-किन क्षेत्रों में निवेश करेंगी। कुछ समय के भीतर ही जिलो में धरातल पर निवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

सेक्टर में 6.60 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद राजस्थान एनर्जी सेक्टर में सरप्लस की श्रेणी में होगा। इससे न सिर्फ राजस्थान की जनता को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर डिस्कॉम भी घाटे से बाहर आ सकेगा।

पीएम मोदी के विजन को साकार कर रहे सीएम भजनलाल

राजस्थान की भजनलाल सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को फॉलो कर रही है। पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर बड़े काम किए हैं। आदर्श सौर ग्राम का काम तेज गति से चल रहा है। पीएम मोदी ने एनर्जी को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसमें राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सीएम भजनलाल ने राइजिंग राजस्थान समिट में पूरा फोकस एनर्जी के क्षेत्र में किया है। इसकी बदौलत ही 19 लाख करोड़ से अधिक निवेश के एमओयू सिर्फ एनर्जी के क्षेत्र में किए गए हैं। सीएम भजनलाल ने इस सपने को साकार करने के संबंध में कहा कि सरकार बनते ही हमने सुधार के प्रयास किए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान ऊर्जा सेक्टर में सरप्लस बने। हमने कई ज्वाइंट वेंचर की स्वीकृति जारी की है। समय पर कार्य हमारी प्राथमिकता है। बजट को धरातल पर उतारने

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को देश में पहले नंबर का राज्य बनाना चाहते हैं। हम बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली अन्य राज्यों को बेचने वाले बनने की ओर अग्रसर है।

- भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

के लिए सरकार काम कर रही है। सरकारी भवनों पर 1000 मेगावाट के रुफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं ।

ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को नंबर वन बनाने का लक्ष्य

सीएम भजनलाल शर्मा का लक्ष्य है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर वन बने। इसके लिए सौर ऊर्जा को हथियार बनाया गया है। राज्य में 2245 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान में 325 दिन से अधिक अच्छी धूप रहती है। राजस्थान के पास सोलर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में असीमित अवसर हैं। ऐसे में सरकार का लक्ष्य राजस्थान को एनर्जी-सरप्लस राज्य बनाना है जो न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों और देशों की मांगों को भी पूरा करने में भी सक्षम हो।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। हम ऊर्जा के सेक्टर में राजस्थान को देश में पहले नंबर का राज्य बनाना चाहते हैं। हम बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली अन्य राज्यों को बेचने वाले बनने की ओर अग्रसर है। सरकार जल्द ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लाएगी। जिससे ऊर्जा क्षेत्र में कई नए संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पांच साल के भीतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी 350 बिलियन डॉलर

राजस्थान का विकास जितना आजादी के बाद अब तक हुआ है, उतने ही विकास का लक्ष्य आगामी पांच साल के भीतर रखा गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पांच साल के भीतर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस सफर में 'राइजिंग राजस्थान समिट' एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। वर्तमान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था 180 बिलियन डॉलर की है। भजनलाल सरकार अपने पहले साल से ही अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार विकसित राजस्थान-2047 पर काम कर रही है।

निवेशकों के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम

प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को लुभाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भजनलाल सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव भी कर रही है। इंवेस्टर्स मीट में निवेशकों से सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है। विकास और समृद्धि के लिए हमने एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया है। हम न केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। इसके लिए

निवेश की शर्तों को सरल बनाते हुए कारोबार के लिए औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण और उसके विकास को सुगम बनाया गया है। लैंड एग्रीगेशन एंड मॉनेटाइजेशन पॉलिसी तथा निजी औद्योगिक पार्क योजना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे व्यापारियों को अपने कारोबार को विस्तार देने में भी अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। भाजपा सरकार का ध्यान केवल निवेशकों के साथ एमओयू साइन करने पर नहीं अपितु उनके लिए धरातल पर ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ बिजनेस तथा कॉस्ट ऑफ बिजनेस आदि महत्वपूर्ण नीतिगत कारोबारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मंजूरी लेने की प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

सीएम भजनलाल ने खुद संभाली निवेश की कमान

राइजिंग राजस्थान को लेकर रिकॉर्ड एमओयू के पीछे सीएम भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता है। सीएम ने खुद निवेश लाने की कमान संभाली है। इसके लिए देश-विदेश के मैराथन दौरे किए। इसके अलावा बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों के साथ वार्ताएं की। इंवेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर, इटली, दक्षिण कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, कतर, ब्राजील, तुर्की, स्पेन तथा स्विटजरलैंड देशों के राजदूतों तथा राजनयिकों के साथ राउंड टेबल वार्ता की गई है। इसके माध्यम से उन्होंने निवेशकों के लिए भारत में हो रहे नीतिगत कारोबारी परिवर्तनों की जानकारी साझा की।

इन क्षेत्रों में निवेश पर राज्य सरकार का जोर

भजनलाल सरकार ने लगातार रोड शो और इंवेस्टर्स मीट के जरिए कृषि, खनिज, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, सौर ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, ईवी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टार्टअप आदि क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित किया है। समिट के माध्यम से पेट्रो केमिकल, रत्न तथा आभूषण उद्योग, पत्थर उद्योग, तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजस्थान में निवेशकों को सभी प्रकार की सिंगल विंडो आधारित सुविधाओं को प्रदान करने का भरोसा दिया है। भजनलाल सरकार का मानना है कि राजस्थान के पास प्राकृतिक रूप से सूर्य, भूमि तथा हवा की उपलब्धता है। जिसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। सरकार अब 'पधारो म्हारे देश' की थीम पर इस क्षेत्र के विकास के साथ-साथ भविष्योनमुखी समग्र विकास चाहती है।

औद्योगिक क्षेत्रों के हिसाब से पार्कों का होगा निर्माण

निवेशकों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखते हुए समूचे राजस्थान में कंट्री स्पेसिफिक जोन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पार्क, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्यूफैक्चरिंग पार्क, स्टोन पार्क तथा ऑटोमोबाइल पार्क का निर्माण होगा। इसके साथ ही ईज ऑफ बिजनेस तथा कॉस्ट ऑफ बिजनेस पर आधारित क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, 'हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां राजस्थान न केवल आर्थिक रुप से समृद्ध हो बल्कि समावेशी तथा सतत विकास का एक मानक भी स्थापित करे। राजस्थान असीम संभावनाओं की भूमि है, जिसका एक मजबूत ढांचागत आधार है। इसके साथ ऐसी सरकार है जो निवेशकों के साथ साझेदारी करने को तत्पर है।'

'एक जिला एक उत्पाद' योजना बनेगी सफलता की सूत्र

'राइजिंग राजस्थान समिट 2024' की सफलता के लिए सरकार 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को माइक्रो लेवल पर स्थापित करेगी। इसके लिए सबसे अधिक तेजी से राजस्थान के अंदर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक जिले से दूसरे जिले को तीव्र कनेक्टिविटी के विभिन्न माध्यमों के जरिये आसानी से जोड़ा जा सके। माल ढुलाई के लिए एक आसान मूलभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। राजमार्गों के किनारे ही बड़े-बड़े औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। इनमें स्थानीय जिले के उत्पादों को विश्वस्तर पर पहुंचाने के लिए ईज ऑफ बिजनेस तथा कॉस्ट ऑफ बिजनेस आधारित उत्पादन संरचना का विकास होगा।

समिट को सफल बनाने की इन पर है जिम्मेदारी

'राइजिंग राजस्थान समिट 2024' आयोजन को सफल बनाने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण मंत्रियों, अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी संस्थाएं बेहतर सामंजस्य के साथ दिन-रात एक साथ लगी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से सीएम भजन लाल के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, राजस्थान सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, उद्योग विभाग के कमिश्नर रोहित गुप्ता के साथ ही सरकार के कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी सम्मिलित हैं। उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इंवेस्टमेंट प्रमोशन तथा राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपना दायित्व निभा रहे हैं, जिसकी नोडल एजेंसी के रूप में ब्यूरो ऑफ इंवेस्टमेंट प्रमोशन का काम कर रही है। ■

ब्रांड पायलट...

कांग्रेस सरकार का वो दौर याद कीजिए जब सचिन पायलट को नकारा-निकम्मा कहा गया। उन्हें बिना जनाधार वाला नेता बताया गया

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

राजस्थान में राजनेता बहुत हैं लेकिन राजनीति में ब्रांड सिर्फ पायलट हैं। इनके सरनेम भर से प्रत्याशी जीत जाता है। पिछली कांग्रेस सरकार में पायलट के खिलाफ रची गई साजिशों के बावजूद ब्रांड पायलट अपने शिखर पर है। इसने सीएम भजनलाल की सुनामी के सामने कांग्रेस की मिट्टी पलीत होने से बचा ली। कांग्रेस सरकार का वो दौर याद कीजिए जब सचिन पायलट को नकारा-निकम्मा कहा गया। उन्हें बिना जनाधार वाला नेता बताया गया। लेकिन हर चुनाव में वही सचिन पायलट कांग्रेस की इज्जत बचा रहे हैं। भजनलाल सरकार के सामने उपचुनाव में कांग्रेस की इज्जत बचाने का काम भी सचिन पायलट ने किया है।

भजनलाल की सुनामी के आगे नहीं टिक पाए विरोधी

राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों से पहले विरोधी कह रहे थे कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सीटें एक से दो हो जाएं तो बड़ी बात होगी। क्योंकि जिन सात सीटों पर उप चुनाव हुए थे, उनमें से पहले सिर्फ सलूंबर की सीट भाजपा के पास थी। लेकिन सीएम भजनलाल की सुनामी के सामने एक भी विरोधी नहीं टिक पाया। इन सात सीटों में से कांग्रेस ने 2023 में चार सीटें जीते थीं। लेकिन इस बार कांग्रेस

सिर्फ एक सीट जीत सकी है। जबकि चार सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। किसी भी उपचुनाव में कांग्रेस का यह शर्मनाक प्रदर्शन है।

सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खींवसर, झुंझुनूं और रामगढ़ में परिवारवाद मठाधीशी को खत्म कर दिया गया है। हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को खींवसर में नहीं जिता पाए। उन्हें अपने जीवन की सबसे करारी हार झेलनी पड़ी है। हनुमान बेनीवाल चुनावों से पहले कह रहे थे कि मेरे हाथ में जीत की रेखा है। उसे भजनलाल शर्मा ने मिटा दिया है। करीब 14 हजार वोटों से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा खींवसर में एक चूहे को पकड़कर शेर बनाया था। जिसे जनता ने फिर से चूहा बना दिया है।

बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला की शर्मनाक हार

बृजेंद्र ओला के बारे में कहा जाता है कि झुंझनू में ओला परिवार न हो तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए। लेकिन अब ओला परिवार भी भजनलाल शर्मा की सुनामी के सामने बेअसर नजर आया है। बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला की शर्मनाक हार हुई है। भाजपा के राजेंद्र भांबू ने अमित ओला को रिकॉर्ड 43 हजार वोटों से हराया है। जबकि बृजेंद्र ओला इसी सीट पर 2023 में करीब 27 हजार वोटों से जीते थे। इससे 21 साल से झुंझुनूं में कायम ओला परिवार और कांग्रेस का किला बुरी तरह से ढह गया है। इसके साथ ही यह मिथ भी खत्म हो गया है कि झुंझुनूं से ओला परिवार को हराया नहीं जा सकता है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि झुंझुनूं में ऐसा लगता था कि एक परिवार की बपौती है। किसी तीसरे को झुंझुनूं में राजनीति करने का अधिकार नहीं था। यहां से भाजपा विधायक बने लंबा समय हो गया था। लेकिन इस बार हमने यह चुनाव बड़े अंतर से जीता है।

देवली-उनियारा में भी कांग्रेस का अंत

उपचुनावों में देवली-उनियारा सीट पर सबकी नजर थी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने पर जमकर बवाल हुआ था। इस सीट पर 2023 में कांग्रेस ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा

> ■ उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह ब्रांड पायलट है जो कि सीएम भजनलाल की सुनामी में भी कांग्रेस को बचा ले गए
>
> ■ सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वह नाकाम रहे

के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने नरेश मीणा को रिकॉर्ड वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने नरेश मीणा को लेकर कहा है कि वहां एक लंपट नेता कानून से खिलवाड़ करता है। हम उसे बताएंगे की कानून उसके साथ क्या कर सकता है। मुख्यमंत्री की पहचान कानून व्यवस्था को मजबूत करने की है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसे सबक सिखाया जाएगा।

रामगढ़ में भी कांग्रेस को कर दिया नेस्तनाबूत

रामगढ़ से विधानसभा चुनाव 2023 में जुबेर खान ने 19,696 वोटों से जीत प्राप्त की थी। उनके निधन के बाद रामगढ़ में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस ने जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को टिकट दिया। तब कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रामगढ़ में हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आर्यन खान के साथ सिंपैथी फैक्टर भी था। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने रामगढ़ में भी परिवारवाद को हरा दिया। भाजपा के सुखवंत सिंह ने आर्यन खान को रिकॉर्ड 13 हजार वोटों से हराया। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि रामगढ़ में पाकिस्तानियों के मैरिज सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम यहां का विधायक करता था। अगर उनका पुत्र जीत जाता तो एक नई पीढ़ी का आतंक लेकर आते।

कांग्रेस की इज्जत बचा पाए सिर्फ ब्रांड पायलट

कांग्रेस को उपचुनाव में सात में से छह सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ दौसा सीट पर दीनदयाल बैरवा की जीत ने कांग्रेस की इज्जत बचा ली। उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह ब्रांड पायलट है जो कि सीएम भजनलाल की सुनामी में भी कांग्रेस को बचा ले गए। कांग्रेस ने दौसा में टिकट सचिन पायलट के करीबी दीनदयाल बैरवा को दिया था। सचिन पायलट का करीबी होने के चलते उत्साह के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और दीनदयाल बैरवा को जीत दिला दी। इसके अलावा खुद सचिन पायलट ने दौसा की कमान संभाली थी। उपचुनाव के आखिरी समय में अपना काफी वक्त दिया। हालांकि यहां पर कांग्रेस को मामूली से अंतर से जीत प्राप्त हुई, अन्यथा भजनलाल की सुनामी में यह किला भी ढह जाता। 2023 में मुरारीलाल मीणा ने दौसा सीट 31 हजार वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार यह जीत सिर्फ करीब दो हजार वोट से हुई है। दौसा में जीत के बाद सचिन पायलट ने कहा कि उपचुनाव परिणामों को हम विनम्रता से स्वीकारते हैं। दौसा में कांग्रेस पर जनता ने फिर भरोसा जताया है। दीनदयाल बैरवा आपकी आवाज विधानसभा में उठाते रहेंगे।

डोटासरा का गमछा डांस पूरी तरह से फेल

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा डांस पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। उनके नेतृत्व में दूसरी बार कांग्रेस ने हार का मजा चखा है। जबकि एक बार भी कांग्रेस उनके नेतृत्व में जीत नहीं पाई है। सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार के समय पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की ठहराई गई। उस वक्त भी गोविंद सिंह डोटासरा को पद से हटाने की मांग प्रदेश कांग्रेस के अंदर उठी थी। तब अशोक गहलोत को पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उपचुनावों के इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। ऐसे में फिर से गोविंद सिंह डोटासरा को पद से हटाने की आवाज उठने लगी है। वहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी उपचुनावों में हार के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा है कि उपचुनावों में हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ■

गहलोत सरकार ने किया था राजस्थान में रामबाग के चूहों जैसा काम

शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था को लचर कर प्रदेश का विकास रोका

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

जयपुर। प्रदेश की राजधानी में जिस तरह रामबाग को चूहों ने खोखला किया, उसी तरह से कांग्रेस सरकार के समय में अशोक गहलोत ने राजस्थान को खोखला कर दिया था। राजस्थान के युवाओं के सपनों को खोखला करने का काम कांग्रेस सरकार में योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इतना ही नहीं कानूनी तौर पर भी प्रदेश को खोखला किया गया। इसी वजह से कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में भी नंबर वन था। कांग्रेस ने युवाओं, छात्रों, महिलाओं, मरीजों और गरीबों के साथ छल किया। इसी छल को ढकने और प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त की योजनाएं जारी की गईं और उनकी आड़ में राजस्थान को बेचा गया।

युवाओं के सपनों और शिक्षा व्यवस्था का सौदा किया

राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार की ओर से तृतीय

श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रीट का आयोजन किया गया। लेकिन भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया गया। रीट परीक्षा के लिए बनाए गए जिला समन्वयक प्रदीप पाराशर ने ही पांच करोड़ रुपये में पेपर बेच दिया। इसमें गहलोत सरकार से जुड़े कई नेताओं के नाम सामने आए। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से रीट की तैयारी कर रहे तमाम प्रतिभावान युवाओं के सपने टूट गए। इसके साथ ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गलत हाथों में चली गई। ऐसे लोग भर्ती हो गए जो कि शिक्षक बनने के लायक भी नहीं थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि वह राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा को किस स्तर पर लेकर जाते? स्कूलों में वह छात्रों को क्या पढ़ाते? पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला करने में जुटी गहलोत सरकार और क्या करती, सोच से भी परे है।

राजस्थान की कानून व्यवस्था को कर दिया कमजोर

गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के राज में सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर खुलेआम 20 से 40 लाख रुपये में बेचा गया। जिन लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता था, वह सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में टॉप कर गए। इसमें भी कांग्रेस सरकार से जुड़े तमाम लोग गिरफ्तार हुए। फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर बनने वाले व्यक्तियों से अब आप कानून व्यवस्था मजबूत करने की उम्मीद करेंगे या भ्रष्टाचार फैलाने की? जिन लोगों ने 40 से 50 लाख रुपये में सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था, अब वह घर वालों के लिए कमाई करने में जुटेंगे या प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? गहलोत सरकार की लचर और भ्रष्ट प्रणाली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कई साल पीछे पहुंचा दिया है। अगले कई सालों तक कानून व्यवस्था के मजबूत होने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है।

एक-एक करोड़ रुपये लेकर फर्जी डॉक्टर बनाए

गहलोत सरकार के समय में राजस्थान मेडिकल काउंसिल तक को भी बेचने से गुरेज नहीं किया गया। 12वीं पास लोगों को जाली कागजों की मदद से डॉक्टर बना दिया गया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक-एक करोड़ रुपये तक वसूले। प्रदेश में 98 अयोग्य छात्रों को करोड़ों रुपये के बदले गायनी और सर्जन जैसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना दिया। इसमें राजस्थान मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा तक शामिल था। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद वर्तमान भाजपा सरकार ने सख्ती की। सरकार ने रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया। अगर यही सख्ती गहलोत सरकार के समय बरती गई होती तो आज प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होती। पिछली सरकार में बने फर्जी डॉक्टर राजस्थान में न जाने कितने मरीजों की जान ले चुके हैं। ऐसे डॉक्टर राजस्थान में मौत का तांडव मचा रहे हैं।

रीट लीक में शामिल 130 लोग हुए गिरफ्तार

कांग्रेस सरकार के समय में पेपर लीक करने वाले माफिया की कमर तोड़ने का काम भजनलाल सरकार ने मजबूती से किया है। भजनलाल सरकार की एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 130 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ गंगापुर सिटी कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है।

सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भर्ती 44 ट्रेनी गिरफ्तार

भजनलाल सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म किया जा रहा है। इससे भविष्य में कोई भी पेपर लीक माफिया बनने से पहले और पेपर खरीदने से पहले सौ बार सोचेगा। पेपर लीक से एसआई बनने वाले 44 ट्रेनी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा पेपर लीक करने में शामिल 30 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरपीएससी के सदस्य रह चुके बाबूलाल कटारा और रामू राम राईका भी शामिल हैं। राजस्थान की एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़कर पेपर लीक से भर्ती होने वाले प्रशिक्षुओं को गिरफ्तार कर रही है। ■

■ जिन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता, वह सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में टॉप कर गए।

■ पिछली सरकार में बने फर्जी डॉक्टर राजस्थान में न जाने कितने मरीजों की जान ले चुके हैं।

मेवात क्षेत्र में गौ-तस्करी पर
पूर्ण अंकुश लगाने के लिए
राजस्थान सरकार के
गृह राज्य मंत्री श्री
जवाहर सिंह बेढ़म जी
का कोटि कोटि
आभार।
अभिनंदन
सतवीर सिंह कसाना
भाजपा नेता

महत्वाकांक्षी मजबूरी

केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब के सीएम! भगवंत मान को हटाने की रची साजिश

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के कई राज समय-समय पर जनता के सामने रखे। इनमें सबसे बड़ा राज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पंजाब का सीएम बनने की केजरीवाल की इच्छा से जुड़ा हुआ था। कुमार विश्वास ने सच्चाई जनता के सामने रखते हुए कहा था "अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। मुझसे उन्होंने कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला तो मैं सीएम बनूंगा। इसके लिए फुलका गुट और भगवंत मान गुट में लड़ाई करवा दूंगा। तब पंजाब की जनता की भलाई की बात कहकर भारी मन से दिल्ली के सीएम का पद छोड़ कर पंजाब का सीएम बन जाऊंगा। मैंने कहा कि पंजाब तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा तो केजरीवाल कहते हैं तुम मुझे पंजाब का सीएम बनते हुए देखोगे।"

कुमार विश्वास ने जब यह किस्सा साझा किया, उस वक्त बदकिस्मती से पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद कुमार विश्वास ने यह राज खोल दिया तो बहुमत मिलने पर भी अरविंद केजरीवाल की यह हसरत अधूरी रह गई। लेकिन अब फिर से हालात इस तरह के पैदा किए गए हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकें। अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर कि अब वह जनता की अदालत में जाएंगे, दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वहां से दोबारा आशीर्वाद मिलने के बाद ही सीएम बनेंगे। तब तक दिल्ली की सीएम आतिशी रहेंगी।

"मैंने कहा कि पंजाब तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा तो केजरीवाल कहते हैं तुम मुझे पंजाब का सीएम बनते हुए देखोगे।"

- कुमार विश्वास

वहीं, पंजाब में सीएम भगवंत मान को कमजोर करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान के पसंदीदा अधिकारियों को एक-एक करके रवाना किया जा रहा है। इसके तहत ही सीएम भगवंत मान के खास ओएसडी ओंकार सिंह को हटा दिया गया है। भगवंत मान की विधानसभा सीट धुरी का पूरा कामकाज ओंकार सिंह ही देखते थे। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग के ओएसडी मंजीत सिंह सिद्धू को भी हटा दिया गया है। इसके पीछे पूरा खेल पंजाब की मीडिया पर कब्जा करना है, ताकि वो केजरीवाल के इशारे पर काम करे।

भगवंत मान की कार्यशैली पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली से केजरीवाल के खास लोगों को भेजा जा रहा है। इनमें सबसे पहला नाम बिभव कुमार का है। यह वही बिभव कुमार हैं जो कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल

के साथ पिटाई के मामले में जेल से जमानत पर बाहर हैं। इन्हें अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता है। केजरीवाल की तरफ से यही मंत्रियों से लेकर विधायक और नेताओं को आदेश देते थे। पंजाब सरकार में इन्हें ओएसडी बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल कांड के बाद और केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद बिभव कुमार खुलेआम नजर आ रहे हैं।

दूसरा नाम विजय नायर का है। वही विजय नायर जो कि शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। शराब घोटाले में जेल जाने से पहले विजय नायर ही आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करते थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कम्यूनिकेशन इंचार्ज थे। इन्हें भी अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में इन्हें भी पंजाब सरकार में बड़े पद पर भेजने की तैयारी है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपने दो खास लोगों के माध्यम से पूरी सरकार को नियंत्रण में लेना चाहते हैं और पंजाब विधानसभा चुनावों तक इसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं।

सूत्रों की मानें तो ऐसी योजना है कि भगवंत मान की तबीयत का हवाला देकर किसी अन्य व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद आसानी से अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकें। इसका पहला प्रयास सफलतापूर्वक किया जा चुका है। भगवंत मान के बीमार पड़ने पर खबरें प्लांट की गईं कि उन्हें सीएम पद से हटाया जा रहा है। खास बात है कि यह खबरें दिल्ली से आम आदमी पार्टी की मीडिया विंग ने प्लांट करवाई थीं। इसके जरिए आंकलन किया

■ भगवंत मान के पसंदीदा अधिकारियों को एक-एक करके रवाना किया जा रहा है।

■ योजना है कि भगवंत मान की तबीयत का हवाला देकर किसी अन्य व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा।

■ भगवंत मान की कार्यशैली पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली से केजरीवाल के खास लोगों को भेजा जा रहा है।

गया था कि भगवंत मान को हटाने पर किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं।

केजरीवाल के लिए पंजाब का सीएम बनना आसान

कुमार विश्वास ने जो किस्सा अरविंद केजरीवाल की साजिश का साझा किया था, उसके लिए काफी हद तक हालात तैयार किए जा चुके हैं। क्योंकि दिल्ली के सीएम पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत या हार मिलने के बाद भी केजरीवाल कह सकते हैं कि अब पंजाब की जनता की अदालत में जाऊंगा। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिलती, तब तक कहीं का भी सीएम नहीं बनूंगा। ऐसे में आतिशी ही दिल्ली की सीएम बनी रहेंगी। पंजाब में जीत मिलने के बाद नई कहानी गढ़ी जा सकती है कि आतिशी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब के लोग-विधायक चाहते हैं कि दिल्ली की तरह ही कुछ दिन वह पंजाब को संभालें। चूंकि दिल्ली और पंजाब के चुनाव हो चुके होंगे तो उनके पास पूरे पांच साल होंगे, पंजाब की सत्ता चलाने के लिए।

पंजाब का सीएम बनने का ख्वाब केजरीवाल की मजबूरी

पंजाब का सीएम बनने का ख्वाब अरविंद केजरीवाल की मजबूरी भी है। क्योंकि दिल्ली में पुलिस से लेकर प्रशासन तक कई विभाग केंद्र सरकार के अधीन हैं। ऐसे में वह दिल्ली के भीतर अपनी मनमानी नहीं कर पाते। केजरीवाल का सपना है कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य का सीएम बनकर केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दें। पंजाब की कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लेकर दूसरे राज्यों में पुलिस भेजकर भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा है। इससे भाजपा नेताओं के खिलाफ बदले की भावना पूरी आम आदमी पार्टी में घर कर गई है। ■

जागरूक प्लस मैगजीन के

नवीन संस्करण के प्रकाशन की

बधाई एवं शुभकामनाएं

Dr.H.N.Sharma campus

PHYSIOTHERAPY Clinic

ऑर्थो न्यूरो चाइल्ड रिहैबिलिटेशन

भरतपुर संभाग का सबसे अत्याधुनिक

फिजियोथैरेपी सेंटर

असमर्थ मरीजों को घर पर

फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध

Decompression Therapy

Dr.V.N.Sharma BPT(Dmrt)

Mob.:- 9772089522, 7014192061

Add:- Dr.H.N.Sharma Campus Near City kotwali Bharatpur

कांग्रेस के मोदी विरोधी एजेंडे की खुल गई पोल, किसान नेता की जमानत जब्त

"हरियाणा की जनता ने अपने वोट से फैसला सुना दिया है कि कांग्रेस हवा हवाई बात कर रही थी"

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के नतीजों से सभी हैरान हैं। चुनाव से पहले जिस हवा का रुख कांग्रेस की तरफ बताया जा रहा था, वह भाजपा की तरफ निकला। इसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस की हार के बाद विरोधी नेता ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हरियाणा में कई ऐसे मुद्दे रहे जो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी ये हश्र कैसे हो गया? असल में चुनाव के बाद कांग्रेस के मोदी विरोधी एजेंडे का एक-एक करके पर्दाफाश हुआ है।

कांग्रेस की चुनाव आयोग को चिट्ठी

हरियाणा की जनता ने अपने वोट से फैसला सुना दिया है कि कांग्रेस हवा हवाई बात कर रही थी, जबकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो भाजपा की पकड़ काफी मजबूत निकली। कांग्रेस की हार के बाद विपक्ष बौखला उठा और अजीबोगरीब बयानबाजी कर हार का ठीकरा अपने सिर से हटाने की कोशिश में लगा रहा। मतगणना के दिन ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईवीएम की बैटरी पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की ओर से 20 सीटों पर धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई। लेकिन कांग्रेस की पोल खुल चुकी थी। हरियाणा की जनता पहले से जानती थी कि कांग्रेस मोदी विरोधी एजेंडा चलाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी और कांग्रेस के झांसे में नहीं आई।

कांग्रेस ने तीन मुद्दों पर लड़ा चुनाव

कांग्रेस ने हरियाणा में मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। इनमें पहला मुद्दा था किसानों का, दूसरा पहलवानों का और तीसरा अग्निवीर योजना का। तीनों मुद्दे महीनों नहीं, बल्कि वर्षों से चलाए जा रहे थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि इतने बड़े मुद्दे होने के बाद भाजपा की जीत असंभव है, लेकिन जनता की अदालत ने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस के इन मुद्दों की पोल भी अब खुलती जा रही है। पार्टी ने मोदी को हराने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वह धरा का धरा रह गया है।

किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही थी कांग्रेस

कांग्रेस को सबसे अधिक फायदा किसानों के मुद्दे पर

"भूपेंद्र ने किसानों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि हम कहीं के नहीं बचे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष के नेता पद से हटा देना चाहिए।"

- गुरनाम चढूनी

मिलने की संभावना थी। किसानों से जनता की भावना जुड़ी होती है। हरियाणा के किसान पिछले तीन-चार वर्षों से भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। महीनों से सिंधू बॉर्डर को बंद कर रखा गया था, ताकि दिल्ली में पहुंच कर अव्यवस्था न फैलाएं। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस की पोल खुली तो एक-एक बात आईने की तरह साफ हो गई है। अपने आप को किसान कहने वाले लोगों का काला चेहरा भी जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस ने किस तरह किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की, इसका खुलासा भी हो गया।

किसान नेता चढूनी को मिले सिर्फ 1170 वोट

कांग्रेस ने हरियाणा से भाजपा का सफाया करने के लिए चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन अफसोस यह कामयाब नहीं हो सकी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। किसान नेता गुरनाम चढूनी संयुक्त संघर्ष पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र की पिहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। अगर धरना-प्रदर्शन करने वालों के साथ जनता की भावना होती, तो, चढूनी को जीत मिलनी चाहिए थी। क्योंकि चढूनी उनके लीडर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकर हैरानी होगी कि पिहोवा की जनता ने चढूनी को सिर्फ 1170 वोट दिए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इससे साफ है कि हरियाणा की जनता ने किसानों के नाम पर वोट मांगने वालों की परख कर ली थी और उनका सफाया करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

'माहौल का फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस'

हरियाणा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद किसान नेता गुरनाम चढूनी ने जो खुलासे किए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते रहे, उन सभी आरोपों का एक पल में खुलासा हो गया। चढूनी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कहा कि हरियाणा में माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सकी। हरियाणा के किसानों ने कांग्रेस को उसके पक्ष में माहौल बनाकर दिया, लेकिन कांग्रेस फिर भी हार गई। कांग्रेस ने प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा

को सौंप दी, उन पर काफी भरोसा कर बैठे, इसलिए कांग्रेस की हार हुई है।

खुद के जाल में फंस गई कांग्रेस

गुरनाम चढूनी ने कहा कि हरियाणा में जो भी माहौल बनाया, किसानों ने बनाकर दिया। फिर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। उनके बयान से यह साफ हो गया कि किसानों के प्रदर्शन का मकसद सिर्फ चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाना और भाजपा की सरकार गिराने का था। जानबूझकर एक नेता को आगे किया गया और उसके नेतृत्व में खुद किसान बताने वाले लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस ने किसानों को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी और भाजपा पर हमला बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई और भाजपा ने फिर से सरकार बना ली। कांग्रेस ने हरियाणा की जनता को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया था, वह उस जाल में खुद फंस गई।

चढूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा

उधर, गुरनाम चढूनी ने हार का ठीकरा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ते हुए कई बड़े आरोप भी लगाए। चढूनी ने कहा कि भूपेंद्र ने हरियाणा में किसी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने दिया। किसानों ने माहौल बनाने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी किसानों के कई बार टिकट मांगने के बावजूद वह एक भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं हुए। उधर, आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं करने दिया, जो पहले गठबंधन हो चुका था उसे भी तोड़ दिया। यही कारण है कि कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा और किसानों के बीच पहले से ही विरोध चल रहा है, अब किसान कहां जाएं? भूपेंद्र ने किसानों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि हम कहीं के नहीं बचे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष के नेता पद से हटा देना चाहिए।

■ "कांग्रेस ने किस तरह किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की, इसका खुलासा भी हो गया।"

■ "पहले हरियाणा में सिर्फ 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 24 कर दिया गया"

जनता ने रमेश दलाल को भी दिखाया आइना

सिर्फ गुरनाम चढूनी ने ही नहीं, बल्कि एक और किसान नेता रमेश दलाल ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन जनता ने उन्हें भी आइना दिखाने का काम किया। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से रमेश दलाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिन्हें सिर्फ 4745 वोट मिले। इस सीट से एक और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून खड़े हुए थे, जिन्हें जीत मिली। जानकर हैरानी होगी कि राजेश जून और रमेश दलाल के बीच वोटों का अंतर 68446 रहा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान नेता रमेश दलाल कितनी बुरी तरह से हारे। वह दूसरे स्थान पर भी नहीं आ सके, बल्कि बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए सभी प्रत्याशियों में पांचवें स्थान पर रहे।

24 फसलों पर दी एमएसपी की गारंटी

कांग्रेस की हार के बाद जिस तरह से सभी के बयान आए, उससे साफ हो गया कि किसानों का प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस की चाल थी, जिसे भाजपा को हराने के लिए चलाया जा रहा था। यही कारण है कि तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए, फिर भी किसान प्रदर्शन करते रहे। पहले हरियाणा में सिर्फ 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 24 कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था कि अब 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बावजूद इसके कांग्रेस एमएसपी का मुद्दा उठाती रही, जो जनता को समझ आ रहा था। इसलिए जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया।

हरियाणा में किसके पास कितनी सीटें

प्रदेश में भाजपा को सरकार बनाने के लिए किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता थी। भाजपा को 48 सीटें मिलीं और बहुमत हासिल कर सरकार में आ गई। इसके बाद में कई निर्दलीय उम्मीदवार भी भाजपा में शामिल हो गए, जिसमें चर्चित सावित्री जिंदल भी शामिल हैं। 70 सीटों से बहुमत से ज्यादा हासिल करने का दावा करने वाली कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर ही अटक गई। ■

राजस्थान के बाद हरियाणा को भी ले डूबे अशोक गहलोत, बुजुर्ग लॉबी कर रही कांग्रेस को बर्बाद

देश में एक हवा बनाई गई है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी एक मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

कांग्रेस का शासन एक के बाद एक कई राज्यों से खत्म होता जा रहा है। साल 2014 तक कांग्रेस की जो रफ्तार थी, वह भाजपा के केंद्र में आने के बाद लगभग खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद कांग्रेस हाई कमान ने हरियाणा चुनाव में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को सौंपी। अब गहलोत ने हरियाणा में भी कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। हरियाणा में कई ऐसे मुद्दे भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे थे, जो पार्टी को आसानी से जीत दिला

सकते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा।

विधानसभा में नहीं चला लोकसभा वाला जादू

देश में हवा बनाई गई है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी एक मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में फिर से कांग्रेस को लेकर भरोसा पैदा होने लगा है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव वाला जादू विधानसभा में भी चलेगा, लेकिन हरियाणा में मिली करारी हार के बाद हाई कमान खुद यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि नतीजे भाजपा के पक्ष में कैसे चले गए? हरियाणा में कांग्रेस को मिली करारी हार कई इशारे कर रही है। मीडिया और राजनेता अपने-अपने हिसाब से कांग्रेस की हार का कारण बताते नहीं थक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठता है कि पूर्व सीएम गहलोत का हरियाणा में कांग्रेस की हार में कितना योगदान रहा है?

बुजुर्ग नेताओं को फ्री हैंड देना पड़ा भारी

कांग्रेस हाई कमान ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताया था और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मुख्य ऑब्जर्वर बना दिया, जिसका अंजाम देखा जा सकता है। गहलोत पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में भी अपने जैसे बुजुर्गों की फौज तैयार कर ली और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया। जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देश की जनता तकनीक और औद्योगिक क्षेत्र में विकास चाह रही है और अब एआई का जमाना आ गया है। ऐसे में युवाओं के मुकाबले जनता बुजुर्ग नेताओं के हाथ में राज्य की सत्ता नहीं देना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस में बुजुर्गों की पूरी फौज है।

हरियाणा में भी चलाया बुजुर्गों का फार्मूला

राजस्थान में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में अशोक गहलोत से जनता का भरोसा उठने लगा था, लेकिन फिर भी पार्टी ने नए चेहरे को मौका देने की बजाय गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। हरियाणा में उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस राजस्थान की हार से सीख लेगी और अपने प्लान में बदलाव करेगी, लेकिन हाई कमान ने बदलाव करना तो छोड़िए, यहां भी गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जैसे बुजुर्ग नेता को आगे कर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता को साइड लाइन कर दिया।

लगातार तीसरी बार हुड्डा के नेतृत्व में हारी कांग्रेस

अशोक गहलोत 73 वर्ष के हो चुके हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 77 साल पार

- हरियाणा के मुद्दे जो भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में थे, कांग्रेस इनका फायदा नहीं उठा सकी।
- समय के साथ पार्टी में नए चेहरे को शामिल करना काफी जरूरी हो गया है, नहीं तो कांग्रेस को आगे भी निराशा ही हाथ लगेगी।
- राजस्थान में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में अशोक गहलोत से जनता का भरोसा उठने लगा था

कर गए हैं। हरियाणा में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के चेहरे पर चुनाव लड़ना बेहतर विकल्प हो सकता था, लेकिन पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में भूपेंद्र हुड्डा की निगरानी में मिली करारी हार के बाद भी फिर से उन्हीं के चेहरे पर भरोसा जताया और 2024 का चुनाव भी हार गई। कांग्रेस को हरियाणा में मिली हार से ज्यादा बड़ा झटका लगा है, इसका कारण है हरियाणा के मुद्दे जो भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में थे, कांग्रेस इनका फायदा नहीं उठा सकी।

ज्योतिरादित्य को भी बनाया शिकार

कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं का गुट हर राज्य के छत्रपों को बचाने का काम किया करते हैं। यह कुछ ऐसे होता है कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। इसी फार्मूला के कारण अच्छे नेताओं को कांग्रेस में उबरने का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने यही फार्मूला मध्यप्रदेश में भी अपनाया था। एमपी में भी कमलनाथ को बचाने के लिए पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन कर उनका गला घोंटने का काम किया। जिसके बाद राजनीतिक करियर बचाने के लिए सिंधिया को भाजपा में शामिल होना पड़ा था। एक के बाद एक कई राज्यों में बुजुर्ग नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ने के कारण मिली हार के बाद भी कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रही है।

नए चेहरों को आगे करने की जरूरत

राजस्थान में भी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2023 में हार का सामना करना पड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण अशोक गहलोत को बताया गया। क्योंकि 2018 में राजस्थान की जनता ने युवा सचिन पायलट के नाम पर वोट दिया था। कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं के होने के कारण युवा नेता या फिर जो हकदार हैं, उन्हें बढ़ावा नहीं

मिलना है। यही कारण है कि पार्टी का बंटाधार होता जा रहा है। अशोक गहलोत ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया और हरियाणा में भी वही कर दिखाया, जिसके कारण कांग्रेस की करारी हार हुई। कई परिणामों को नजर में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस को नजर बदलने की जरूरत है। पार्टी अभी भी उन नेताओं को लीड रोल सौंप रही है, जो कभी दिग्गज हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ पार्टी में नए चेहरे को शामिल करना काफी जरूरी हो गया है, नहीं तो कांग्रेस को आगे भी निराशा ही हाथ लगेगी।

राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन

बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी कांग्रेस सिर्फ 70 सीटें ही हासिल कर सकी थी, कांग्रेस ने 199 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। दूसरी ओर भाजपा ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 115 सीटें अपने नाम कर सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा को सरकार बनाने के लिए किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ■

साइबर ठगी का गढ़ मेवात, सरकार और नेता बदलते ही कैसे बिखरने लगा?

जहां जामताड़ा में ठगी लिंक भेजकर होती है, वहीं मेवात से कॉल करके ठगी की जाती थी।

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

प्रदेश की छवि में मेवात कभी एक बदनुमा धब्बे की तरह था। साइबर ठगी के मामलों में मेवात पहले नंबर पर था और पूरी दुनिया में बदनाम झारखंड के जामताड़ा का नंबर भी दूसरे स्थान पर आता था। लेकिन राजस्थान में सरकार बदलते ही हालात बदल गए। साइबर ठग अब ठगी से तौबा-तौबा करने लगे हैं। साइबर ठगों की आलीशान कोठियों पर बुलडोजर चलने लगा है। मेवात में ठगी से पैसा कमाकर रुतबा दिखाने वाले ठग जान बचाने की फिराक में घूम रहे हैं। यह सब चमत्कार सरकार और स्थानीय राजनीति के परिवर्तन से हुआ है।

जामताड़ा वेब सिरीज भले झारखंड की कहानी को दिखाती है लेकिन असल में वह मेवात से मेल खाती है। कुछ समय पहले तक मेवात में साइबर ठगों को राजनेताओं की ओर से संरक्षण दिया जाता था। बड़े-बड़े सफेदपोशों के संरक्षण में साइबर ठगी होती थी। इसके बदले में साइबर ठगी का अधिकांश पैसा इन्हीं सफेदपोशों के पास जाता था। उसी पैसे का इस्तेमाल नेता चुनावों में करते थे। दुनिया के सबसे अमीर देशों में बैठकर देश की बर्बादी का आनंद लेते थे। लेकिन सरकार बदलते ही हालात बदल गए। स्थानीय

राजनीति के बदलते ही ठग अपने ठगी के गढ़ों को छोड़ गए हैं। आइए इसके संबंध में सिलसिलेवार घटनाक्रम जानते हैं।

विधानसभा चुनाव 2023 के साथ दरकने लगा साइबर ठगी का गढ़

डीग क्षेत्र का मेवात इलाका कोरोना काल के बाद से खूब सुर्खियों में रहा है। पहले यह इलाका साइबर ठगी के लिए मशहूर था और अब साइबर ठगों पर हो रही कार्रवाई के लिए। जहां जामताड़ा में ठगी लिंक भेजकर होती है। वहीं मेवात से कॉल करके ठगी की जाती थी। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की गई है।

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम हैं। 2023 तक कामां की विधायक जाहिदा खान और नगर के विधायक वाजिब अली थे। इनसे जुड़े लोगों का नाम समय-समय पर साइबर ठगों को संरक्षण देने के रूप में सामने आया। जाहिदा खान के कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद पुलिस को कभी साइबरों ठगों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट नहीं मिली। साइबर ठगों से त्रस्त कामां और नगर की जनता ने विधानसभा चुनाव 2023 में परिणाम बदल दिए। नगर विधानसभा सीट से जवाहर सिंह बेढ़म और कामां विधानसभा सीट से नौक्षम चौधरी को जिताकर भेजा। इससे अचानक साइबर ठगों को मिल रहा राजनैतिक संरक्षण खत्म हो गया। प्रदेश की सबसे मुश्किल सीटों में से एक नगर में जीत मिलने पर जवाहर सिंह बेढ़म को सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। भजनलाल सरकार का यही कदम साइबर ठगों के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। जवाहर सिंह बेढ़म के मंत्री बनते ही पुलिस को साइबर ठगों और गौ तस्करों पर कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दिया गया। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया कि मेवात में क्राइम रेट 70 फीसदी से घटकर 22 फीसदी पर लुढ़क गया।

■ मेवात में साइबर ठगी पर अंकुश लगाने की पटकथा मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में लिखी गई।

■ मेवात से सात महीने में 70 से अधिक गैंग के एक हजार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

■ ये ठग हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल दिखाकर बेरोजगारों को टारगेट करते हैं और उनसे ठगी करवाते हैं।

सीएमओ में लिखी गई साइबर ठगों पर कार्रवाई की पटकथा

मेवात में साइबर ठगी पर अंकुश लगाने की पटकथा मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में लिखी गई। सीएम भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के नेतृत्व में डीजीपी, डीजी साइबर क्राइम को साफ निर्देश दिए गए कि साइबर क्राइम पर पूरी तरह से कंट्रोल करें। 1 मार्च 2024 को ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू किया गया। आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में मेवात इलाके से बीते सात महीने में 70 से अधिक गैंग के एक हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 123 नाबालिग भी शामिल पाए गए। अधिकतर बच्चे सेक्सटॉर्शन से संबंधित ठगी से जुड़े मिले। आईजी भरतपुर रेंज की टीम ने नाबालिगों से साइबर ठगी करवाने वाले शेरा, मक्की, अब्बास, शब्बीर सहित अन्य गैंग के सरगनाओं की कमर तोड़ दी। साइबर ठगों से पूछताछ में पता चला कि देश के 28 राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले आठ माह में गिरफ्तार ठगों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 5,572 मुकदमे दर्ज हैं।

साइबर ठगों के राजनीतिक संरक्षण की आईजी ने खोली पोल

आईजी राहुल प्रकाश ने पहली बार साइबर ठगों को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण की पोल खोली। उन्होंने मीडिया को बताया कि कई बार परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। पुलिस कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं डरती है। पिछली सरकार में कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस तंत्र में हिस्सेदार थे और ठगों पर कार्रवाई नहीं करने देते थे। इसमें पुलिस से संबंधित लोग भी शामिल थे। अब भजनलाल सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं कि साइबर ठग बचने नहीं चाहिए। जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जो पुलिस पहले थी वही आज है, बस काम करने का अंदाज बदल गया है।

ऐसे ठगी की प्लानिंग करते थे मेवात के साइबर ठग

बीते पांच सालों में मेवात में साइबर अपराध काफी बढ़ा था। इस काम में मुखबिर समेत कई लोग शामिल थे। मुख्य सरगना का काम होता है फर्जी सिम, मोबाइल और बैंक खाते खुलवाना तथा ठगी का शिकार बनाने के लिए लोगों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाना। इसके बाद मैसेंजर द्वारा सेक्सटॉर्शन का वीडियो बनाने वाला गैंग काम में लग जाता है। वे लोगों को अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते है। इसके बाद अलग-अलग राज्यों का साइबर क्राइम अधिकारी बनकर गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। इनके साथ अन्य कामों में मदद करने के लिए दूसरे सदस्य भी होते हैं। इनके जिम्मे एटीएम से पैसे निकालने, मुख्य सरगना के कहने पर गैंग के सदस्यों को उनका हिस्सा पहुंचाने वाले शामिल हैं।

मेवात में इस तरह से होती थी ठगी

सेक्सटॉर्शनः सोशल मीडिया पर लड़की बनकर पहले तो प्यार भरी बातें करते हैं। फिर वीडियो कॉल कर जाल में फंसाने की साजिश होती है। इस तरह की ठगी में अपराधी दूसरे मोबाइल में लड़की की अश्लील वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मोबाइल पर लड़की के साथ स्क्रीन का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपये की ठगी की जा चुकी है।

ओएलएक्सः ओएलएक्स पर फर्नीचर, साइकिल, मोटर साइकिल सहित अन्य सामान को बेचने के लिए ठग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्हें खरीदने की इच्छा जताता है तो सामान बेचने का झांसा देकर ठगी करते हैं। सामान की अच्छी-अच्छी फोटो भेजकर उस व्यक्ति से एडवांस राशि की मांग करते हैं। जाल में फंसकर व्यक्ति एडवांस पैसे उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और ठगी का शिकार बन जाता है।

हेल्थ इंश्योरेंसः जालसाज हेल्थ इंश्योरेंस की रकम देने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पहले तो कहते हैं कि जो इंश्योरेंस करवाया था उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी हुआ था। अब ऑफिस आकर पैसे ले लो। ऑफिस नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं आप इतनी राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो तो हम आपको घर पर ही भिजवा देंगे। इस तरह से जालसाज लोगों के साथ ठगी करते हैं।

बेरोजगारों को पैसे कमाने का लालच देकर करवा रहे ठगी

भरतपुर रेंज पुलिस के मुताबिक मेवात के लोग साइबर ठगी को बिजनेस मानते हैं। अधिकतर लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। सरकार बदलने के बाद सख्ती होने पर अपराध का तरीका बदल रहे हैं। पुलिस की सख्ती के चलते गांव के बड़े साइबर ठग दूसरे स्थानों पर जाकर ठगी कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की ठगी से बचने के लिए हरियाणा बॉर्डर पार कर नूंह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये ठग हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल दिखाकर बेरोजगारों को टारगेट करते हैं और उनसे ठगी करवाते हैं।

इनका फोकस दूसरे राज्यों के लोगों को ठगने पर रहता है क्योंकि दूसरे राज्यों की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने नहीं आती है। भरतपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि हमने संबंधित राज्यों की पुलिस को ई-मेल व साइबर हेल्पलाइन पोर्टल के जरिए गिरफ्तार ठगों की सूचना भिजवाई, इसके बावजूद अन्य राज्यों की पुलिस इन ठगों को गिरफ्तार करके नहीं ले जा रही है। मुकदमों में कार्रवाई नहीं होने से ठगों के हौसले बढ़ रहे हैं। ■

जागरुक प्लस मैगजीन

के नवीन संस्करण के

प्रकाशन

की बधाई एवं शुभकामनायें।

बबीता शर्मा

प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस
प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ

भजनलाल सरकार के 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' ने तोड़ी राजस्थान में गौ तस्करों की कमर

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

- भगवंत मान के पसंदीदा अधिकारियों को एक-एक करके रवाना किया जा रहा है।
- योजना है कि भगवंत मान की तबीयत का हवाला देकर किसी अन्य व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा।
- भगवंत मान की कार्यशैली पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली से केजरीवाल के खास लोगों को भेजा जा रहा है।

प्रदेश की भजनलाल सरकार रामराज्य की अवधारणा के साथ चल रही है। यूपी के योगी मॉडल के आधार पर राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर राज्य में अपराधियों, माफियाओं के विरूद्ध अभियान छेड़ रखा गया है। गौ तस्करों से लेकर पेपर माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सबसे पहले राज्य को अपराध मुक्त किया जाएगा। इसी क्रम में सीएम बनते ही भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मेवात में गौ हत्या और गौ तस्करी पर अंकुश लगाया। पिछली सरकार में गौ तस्करों का दुस्साहस इतना बढ़ चुका था कि पुलिस और प्रशासन को देखते ही सीधे फायरिंग शुरू कर देते थे। गौ तस्करों के इसी आतंक को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' को युद्ध स्तर पर शुरू किया।

जो भी गौ तस्करी का प्रयास करेगा, उसकी रोकथाम के लिए संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं

'ऑपरेशन नंदी प्रहार' ने मचाया गौ तस्करों में हड़कंप

कांग्रेस के शासन काल में अपराध और अपराधी इतने निर्भय हो चुके थे कि राजस्थान के आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। सत्ता और माफियाओं के गठजोड़ ने संगठित अपराध को शिखर पर पहुंचा दिया था। इसमें ही गौ तस्करी और गौ हत्या भी एक प्रमुख संगठित अपराध का रूप ले चुका था। इसने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को इसका अड्डा बना दिया। राजस्थान-

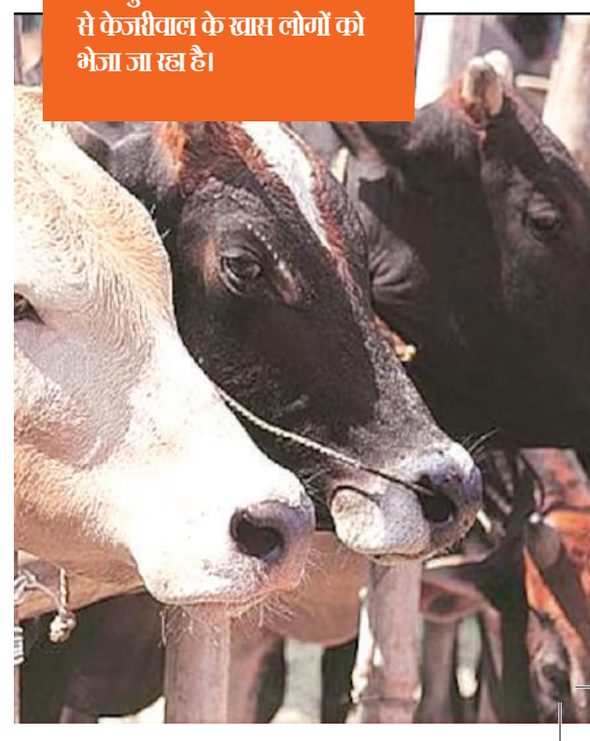

हरियाणा सीमा पर मेवात क्षेत्र में बड़े स्तर पर गौ तस्करी का काम होने लगा। गौ तस्करी के इसी संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए 2013 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने सबसे पहले गौ रक्षक चौकियों का गठन किया था। लेकिन 2018 में गहलोत सरकार आने के बाद स्टाफ की कमी की बात कहकर इन चौकियों को पूर्णतः बंद कर दिया गया। इसे भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले पूरी ताकत से शुरू कर दिया। इसके लिए एक सुनियोजित नीति बनाकर आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' अभियान शुरू किया गया। इसके तहत नौ माह पहले राज्य स्तर पर क्यूआरटी तथा डीएसटी की संयुक्त टीमों का गठन कर दिया गया। इन टीमों का नेतृत्व डीग जिले के एसपी को सौंपा गया। इसके द्वारा गौ तस्करों के विरूद्ध कठोरता से कार्रवाई की जा रही है।

आईजी भरतपुर रेंज ने किया टीमों को सक्रिय

भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने राज्य स्तर पर 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' अभियान के तहत सबसे पहले सात चौकियों को स्थापित किया। पुरानी बंद पड़ी चौकियों में भी पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था को सक्रिय कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में गौ तस्करी के सभी रास्तों को चिह्नित किया। हथियारबंद गौ तस्करों से कठोरता से निपटने के लिए क्यूआरटी तथा डीएसटी टीमों को अत्याधुनिक हथियार तथा उपकरणों से लैस किया। इसमें एके-47 तथा इंसास जैसे अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार दिए गए। इस बारे आईजी राहुल प्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गौ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। पुलिस को गौ तस्करों की गोली का जवाब गोली से देने की पूरी छूट दी गई है। लेकिन गौ तस्करी को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। इस अभियान के बाद ही गौ तस्करों में ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

एक साथ कई जगहों पर क्यूआरटी एक्शन में

राजस्थान में हरियाणा सीमा से लगा डीग जिले का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मेवात गौ तस्करी के लिए सबसे कुख्यात है। यह हरियाणा के सीमावर्ती नूंह जिले का भी प्रमुख मार्ग है। इस क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण यह गौ तस्करी का सबसे बदनाम और अतिसंवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। यहां के अधिकांश स्थानीय लोग गौ तस्करी के साथ ही कई गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। गौ तस्करी रोकने के लिए टीमों के गठन के बाद जयपुर, दौसा, अलवर, कुम्हेर, जुरहरा सहित सीमावर्ती इलाकों में में मुखबिरों की सूचना पर बड़े पैमाने पर नाकाबंदी की गई है। मेवात के घाटमीका में आधी रात को लगाए नाके में ज्वाइंट टीम की गौ तस्करों से सीधी मुठभेड़ हो गई। करीब आठ किमी तक पीछा करने के बाद गौ तस्करों ने खुद को घिरता देख टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर जुबैर पकड़ में आ गया जबकि अन्य साथी तस्कर भागने में सफल रहे।

गौ तस्करों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन

ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों

ने बताया गया कि 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' अभियान के तहत अब तक 40-50 गौ तस्करों को अभिरक्षा में लिया गया है। लगभग 200 गोवंशों को बचा लिया गया है। आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कोई मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अलवर जिले में 38 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। किशनगढ़बाज थाना प्रभारी सहित बीट स्तर से बीट प्रभारी सहित सभी पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। इसके साथ ही चेतावनी दी गई हुए कहा कि लापरवाह पुलिसकर्मियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। किशनगढ़बाज थाने पर कार्रवाई के बाद गौकशी में संलिप्त गौ तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। तिजारा के रूंद गिदावड़ा में यूपी मॉडल पर सबसे पहले बिजली के कनेक्शन काट गए। सरकारी जमीनों पर बनाए गए कच्चे तथा पक्के मकानों के सभी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया।

प्रदेश में अब कोई गौमाता को नहीं कह सकेगा आवारा

'ऑपरेशन नंदी प्रहार' की सफलता से उत्साहित भजनलाल सरकार ने अगले कदम की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान में कोई भी गाय को आवारा नहीं कह सकेगा। सीकर से भाजपा के विधायक गोबर्धन वर्मा ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की तर्ज पर राज्य में गाय को 'राज्यमाता' का दर्जा देने की मांग की थी। इसी मांग पर राज्य के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब गाय को राज्य में आवारा कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा। हम गाय के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित हैं। जिसके लिए एक कानून बनाया जा रहा है। गौमाता हमारी माता हैं, हम यह आज से नहीं वर्षों से पुकारते आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि गाय को राज्य में भी माता का स्थान अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए।

गौ तस्कर इलाका छोड़कर भागेंगे। जो भी गौ तस्करी करेगा उसको सलाखों के पीछे करके इलाज किया जाएगा।

- जवाहर सिंह बेढ़म,
गृह राज्य मंत्री

जवाहर बेढ़म की सक्रियता से मेवात बन रहा गौ तस्कर मुक्त

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म गौ तस्करी के विषय पर सबसे अधिक मुखर और सक्रिय रहे हैं। जवाहर सिंह बेढ़म की चेतावनी का गौ तस्करों पर बड़ा असर पड़ा है। शासन-प्रशासन की मिलीभगत से गौ तस्करी करने वाले तस्करों में भय व्याप्त हो गया है। गृह राज्य मंत्री ने खुले मंच से कहा है कि गौ तस्कर इलाका छोड़कर भागेंगे। जो भी गौ तस्करी करेगा उसको सलाखों के पीछे करके इलाज किया जाएगा। जो भी गौ तस्करी करने का प्रयास करेगा, उसकी रोकथाम के लिए संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार गौवंश की तस्करी के विरूद्ध प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व तय कर रही है। इसके लिए दंड और अर्थदंड के प्रावधान को भी सुनिश्चित कर दिया है। अवैध परिवहन पर कठोरता से प्रहार किया जा रहा है। गौ तस्करों का साहस नहीं कि अब नगर से गाड़ी भी निकाल लें। गौ तस्करों के अंदर पुलिस और प्रशासन का भय व्याप्त हो गया है, जिससे अब किसी भी जिले में गौ तस्करी आसान नहीं है।

सीएम ने दोहराया संगठित अपराधों पर कार्रवाई का संकल्प

सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से 25 अक्तूबर 2024 को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के अवसर पर राज्य की जनता, उद्योगपतियों तथा निवेशकों को भयमुक्त, अपराधमुक्त शासन देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार लोगों को विश्वास दिलाती है कि राज्य कानून के अनुसार ही चलेगा और किसी के भी साथ अन्याय न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आम जनता की भावनाओं तथा आस्था से खिलवाड़ करते हैं और आसमाजिक तत्वों को सह देकर आपस में लड़वाने का षडयंत्र करते हैं। ■

जागरूक प्लस मैगजीन

के नवीन संस्करण के

प्रकाशन

की हार्दिक बधाई एवं

शुभकामनाएं

नेम सिंह जादौन

सरपंच ग्राम पंचायत इकरन, भरतपुर

महाराणा प्रताप को पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय गौरवशाली इतिहास का युगांतकारी कदम

महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के महानायक भी हैं, जिन्हें मुगलों का डटकर सामना करने और अपने साहस के लिए जाना जाता है

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

भारतीय गौरवशाली इतिहास क्या है? इसके वास्तविक नायक कौन-कौन हैं? भले ही इस बारे में आधी या पूरी जानकारी हो, लेकिन किताबों के माध्यम से अब इसकी पुख्ता जानकारी दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा लगता है इसकी पुनर्स्थापना का ऐतिहासिक आरंभ हो चुका है। भाजपा की भजनलाल सरकार ने इस दिशा में अपने चुनावी वादे को पूरा करने की ओर गंभीर कदम उठा लिया है। जबकि केंद्र की मोदी सरकार दो वर्ष पहले ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में ये परिवर्तन कर चुकी है। इसी कड़ी में राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की। नए शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम परिवर्तन में राजस्थान के राजपूत शासकों के गौरव महाराणा प्रताप को सम्मिलित करने के साथ-साथ

महाराष्ट्र के गौरव वीर शिवाजी तथा वीर सावरकर को भी सम्मिलित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का अध्ययन करेगी। इसके बाद समिति राज्य सरकार के समक्ष सुझाव प्रस्तुत करेगी। समीक्षा के पश्चात जो भी गलत तथ्य पाए जाएंगे, उसे हटाएंगे और तथ्यपरक जानकारी जोड़ी जाएगी।

कैसा रहेगा राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव

भजनलाल सरकार का यह कदम इतिहास लेखन की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। भारतीय नायकों को भारतीय गौरवशाली इतिहास में उनका समुचित सम्मानित स्थान मिलेगा। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं और राजस्थान के महानायक भी हैं। उन्हें मुगलों का डटकर सामना करने और अपने साहस के लिए जाना जाता है। अब राजस्थान के स्कूलों में उन्हें अधिक सम्मान के साथ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब किसी भी पाठ्यपुस्तक में अकबर को महान के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा। अकबर को महान पढ़ाने वाले लोग राजस्थान और मेवाड़ के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

महाराणा प्रताप को मिलेगा उनका गौरवशाली स्थान

दो साल पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को शामिल कर एक ऐसा निर्णय लिया, जिसने कांग्रेस की पिछली सभी सरकारों की गलती सुधारने का काम किया। वास्तव में जिस सच्चे इतिहास को देश से छिपाया गया, उसे अब समुचित स्थान दिया जा रहा है। अब बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसे कथित बुद्धिजीवी छिपाते आए थे। इतिहास में जिन महानायकों को सुनियोजित ढंग से छिपाया गया, उन्हें पाठ्यक्रमों का आवश्यक हिस्सा बनाकर पढ़ाया जाएगा। उन्हीं में से एक हैं महाराणा प्रताप, जिनके इतिहास को अकबर को महान बनाकर छिपाया गया।

■ अब किसी भी पाठ्यपुस्तक में अकबर को महान के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा, अकबर को महान पढ़ाने वाले लोग राजस्थान के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

■ कांग्रेस सरकार ने देश के नायकों को मिटाने के लिए इतिहास लेखन का काम सुनियोजित ढंग से वामपंथियों और जिहादी विचारधारा वालों को दिया।

■ शिक्षाविदों ने अपने शोध के माध्यम से हाल के कुछ वर्षों में साफ किया कि वास्तव में हल्दीघाटी का युद्ध अकबर ने नहीं अपितु महाराणा प्रताप ने जीता था।

हल्दीघाटी युद्ध के तथ्यों को करेंगे सुव्यवस्थित

अब महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी में अकबर को हराने के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इतिहास का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। हल्दीघाटी के युद्ध की जानकारियों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इसके समर्थन में कई शिक्षाविदों का मानना है कि कांग्रेस की सरकारों ने सनातन संस्कृति और देश के नायकों को इतिहास से मिटाने के लिए इतिहास लेखन का काम सुनियोजित ढंग से वामपंथियों और जिहादी विचारधारा वाले लोगों को दिया। उन्होंने अपने कुतर्कों के माध्यम से इतिहास को एक विशेष रंग में परोसा।

हल्दीघाटी के विजेता होने का सम्मान मिलेगा

हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं कि हल्दीघाटी के ऐतिहासिक युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई तब से कुछ शिक्षाविदों ने अपने शोध के माध्यम से हाल के कुछ वर्षों में साफ किया कि वास्तव में हल्दीघाटी का युद्ध अकबर ने नहीं अपितु महाराणा प्रताप ने जीता था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के इतिहास विभाग की ओर से इसे विगत

कई वर्षों से पढ़ाया भी जा रहा है। इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो. दिग्विजय भटनागर द्वारा संपादित पुस्तक हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख है।

वहीं, अन्य शोधार्थी डॉ. चंद्रशेखर शर्मा के हल्दीघाटी पर किए गए शोध के अनुसार, 'हल्दीघाटी के युद्ध में जीत किसकी हुई, ये मैं कुछ प्रमाणों के आधार पर समझाता हूं। मुगल सेना को हल्दीघाटी के युद्ध से पहले अकबर ने सख्त दिशानिर्देश दिए थे कि महाराणा प्रताप किसी भी स्थिति में जीवित अथवा मृत चाहिए। किंतु मुगल सेना न तो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ सकी और न ही मृत। इसके अलावा जब मुगल सेनापति मानसिंह युद्ध के पश्चात अकबर के समक्ष दरबार में प्रस्तुत हुआ तब अकबर ने मानसिंह की ड्योढ़ी बंद करने का फरमान सुना दिया (मतलब व्यक्ति राजदरबार में प्रवेश नहीं कर सकता)। अब आप ही बताइये कि जब सेनापति हल्दीघाटी युद्ध में जीतकर ही लौटा था तो अकबर उन्हें इनाम देता, फिर ड्योढ़ी बंद क्यों की? अब इस आधार पर भी बताइये जीत किसकी हुई!'

यही नहीं इस युद्ध के पश्चात भी उस समूचे क्षेत्र पर महाराणा प्रताप के द्वारा ही पट्टे जारी किए जाते रहे। तो प्रश्न उठता है कि पट्टे तो एक शासक ही जारी कर सकता है। जिसके आधिपत्य में वह क्षेत्र हो। अब आप ही बताइए कि हल्दीघाटी के युद्ध में जीत किसकी हुई थी।

राजस्थान के अन्य राजपूत शासकों के गौरव स्थापना का बनेगा आधार

हम सभी के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि महाराणा प्रताप के अन्य पूर्वजों का क्या इतिहास है? तो सर्वप्रथम सातवीं सदी में चित्तौड़ के राजा रहे बप्पा रावल के बारे में बात करते हैं। उस समय सिंध के राजा दाहिर पर मुहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण हुआ। उसने राजा दाहिर की निर्ममता से हत्या कर दी। उसकी हत्या के साथ ही भारतीय इतिहास की सबसे अनैतिक घटना को मुहम्मद बिन कासिम ने घटित किया। राजा दाहिर की हत्या कर कासिम उनकी दो पुत्रियों को अपने साथ यौन दासी बनाकर ले गया और उन्हें अपने खलीफा के सामने उपहार के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये घटना तत्कालीन हिन्दू जनमानस और राजाओं के लिए अकल्पनीय थी कि युद्ध में एक राजा के हार जाने पर कोई जीता हुआ राजा महिलाओं को यौन दासी बनाकर ले जा सकता है। इस घटना ने उस दौर के भारतीय शासकों को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद राजा दाहिर का पुत्र जान बचाकर चित्तौड़ के राजा बप्पा रावल की शरण में आता है। इस घटना को सुनकर बप्पा रावल तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण शासक की शक्ति नहीं हो सकती। यह तो किसी वहशी म्लेच्छों, बलात्कारी तथा लुटेरों का झुंड है, जिनके साथ हमें रक्तरंजित संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने देर न करते हुए परिहार और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाकर लगभग ढाई

लाख की सेना खड़ी कर दी। इसका जोधपुर के एक रणक्षेत्र में लगभग इतने ही बड़े आकार की सेना के साथ युद्ध हुआ। भारत के समृद्ध इतिहास के साथ ही इस युद्ध के अभिलेखों और नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक कर नष्ट कर दिया गया। किंतु कुछ शोधार्थियों द्वारा अरब इतिहास के अभिलेखों को खंगालने पर कहा गया कि इस भीषण युद्ध में अरबों को कहीं सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। मोहम्मद बिन कासिम को बप्पा रावल ईरान तक खदेड़ कर आए। इसके बाद लगभग 500 वर्षों तक कोई इस्लामिक आततायी भारत में नहीं घुस सका। फिर 12वीं सदी से ठीक पहले पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मुहम्मद गौरी को हराया। लेकिन आखिरी युद्ध में छल और धोखे से पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। तब पहली बार इस्लामिक आक्रमण सफल हुआ और वो भारत में प्रवेश कर सके। इस इतिहास को भी फिर से सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

बाबर और अकबर लुटेरे थे

कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वामपंथी इतिहासकारों और जिहादी विचारधारा से प्रेरित लेखकों ने हमारे

इतिहास में अकबर महान का नरेटिव सुनियोजित रूप से गढ़ा। उन्होंने अकबर को महान बाबर का बेटा संबोधित करके प्रस्तुत किया। यही नहीं इसके साथ ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी अपनी एक किताब (डिस्कवरी ऑफ इंडिया) में अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और महान व्यक्तित्व बताते हुए उसकी सफलताओं का गुणगान किया। उन्होंने उसे महिमामंडित करते हुए यहां तक कह दिया कि अकबर ही एकमात्र बादशाह रहा जिसने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का आश्चर्यजनक काम किया। उसकी राजनीतिक और युद्ध क्षमता अद्भुत थी। जबकि देखा जाए तो वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेस सरकार ने बड़ी ही कुटिलता से इस बात को भारतीय जनमानस की चेतना से दूर कर दिया कि बाबर एक आक्रमणकारी लुटेरा था और अकबर उसकी सल्तनत का एक वंशज। इन इतिहासकारों ने इन लुटेरों के अनैतिक लूट, हत्याओं, बलात्कार, व्यभिचारी मानसिकता को उनकी विजय के रूप में प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस को विषैला कर दिया।

लव जिहाद की नींव डालने वाला

वर्ष 1562 में अकबर ने पहली बार अपनी तीसरी पत्नी के रूप में एक हिंदू कछवा राजपूत राजकुमारी से विवाह कर लिया और एक प्रकार से लव जिहाद की नींव डाली। यह भारतीय इतिहास में पहली बार था कि एक मुस्लिम शासक ने हिंदू राजकुमारी से विवाह कर लिया और इसी घटना को उदाहरण बनाकर वामपंथी इतिहासकारों के गिरोहों ने सेक्युलरिज्म का नाम दे दिया। जबकि देखा जाए तो अकबर ने न जाने कितनी महिलाओं को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था, जिन्हें उसने ताकत के बल पर पत्नी बनाया था। यहां तक कि अपने सेनापति बैरम खान की पत्नी को भी बलपूर्वक छीन लिया। उसकी इन पत्नियों के साथ कहीं भी वैवाहिक कार्यक्रम किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। यहां तक की जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह की बात को जोधाबाई से विवाह के रूप में गढ़ा गया है। अभिलेखों में इस तरह का कोई नाम कहीं भी अंकित नहीं पाया गया है। कुछ सूचनाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है जैसलमेर की जिस हिंदू कछवा राजपूत राजकुमारी से अकबर ने विवाह किया, उसी को जोधाबाई बनाकर प्रस्तुत कर दिया। जबकि ऐसा माना जाता है कि अकबर अपनी सभी रानियों में तीसरी पत्नी को सबसे अधिक पसंद करता था, जो बाद में उसके सल्तनत की प्रमुख रानी बनी। जिस अकबर को सेक्युलर बनाकर थोपा गया, वास्तव में उसने ही पहली बार धर्म के आधार पर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इस जजिया कर से बचने के लिए शर्त के रूप में इस्लाम अपनाने को बाध्य किया गया। इस प्रकार देखा जाए तो अकबर का समूचा जीवन व्यभिचारी, आततायी, बलात्कारी शासक के अतिरिक्त कुछ नहीं था और उसे भारतीय इतिहास का महान शासक बनाकर थोप दिया गया। ■

मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार के
गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी
का कोटि कोटि आभार।
अभिनंदन
दौलत सिंह फौजदार
भाजपा नेता,नदबई

प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसा गए अशोक गहलोत। जानिए कर्ज लेकर घी पीने का एक-एक किस्सा

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

राज्य के प्रत्येक नागरिक के सिर पर औसतन 71 हजार रुपये का ऋण हो गया है जो कि वर्ष 2017 में 36,880 रुपये था

राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है, तब से ही आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। वजह है पूर्ववर्ती गहलोत सरकार जो कि प्रदेश को कर्ज के दलदल में छोड़कर चली गई। गहलोत सरकार के कार्यकाल पर आई कैग की रिपोर्ट ने राज्य की आर्थिक दशा का खुलासा किया है और राजनीतिक रूप से हलचल पैदा कर दी है।

कैग ने खोला गहलोत सरकार की आर्थिक गड़बड़ियों का काला चिट्ठा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर कांग्रेस की गहलोत सरकार के पांच सालों में अपनाई गई नीतियों पर वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई। इसमें राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के द्वारा दोहरे भुगतान से जुड़े कई मामलों का खुलासा किया है। इस महत्वपूर्ण प्रणाली के उन्नयन के लिए केंद्रीय एजेंसी एनआईसी ने गहलोत सरकार से 65 करोड़ रुपये मांगे थे। लेकिन इतने संवेदनशील कार्य के अपग्रेडेशन का काम एक निजी कंपनी को सौंप दिया। इसके अलावा मनमाने ढंग से उस पर 10 गुना अधिक खर्च कर दिया गया। इस वार्षिक रिपोर्ट में राज्यकर्मियों को मिलने वाले जीपीएफ तथा एनपीएस में भारी भ्रष्टाचार के संकेत दिए गए हैं।

देश का छठा सबसे अधिक कर्ज लेने वाला राज्य

रिजर्व बैंक के आंकड़ों तथा लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ऋण के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश का छठा सबसे अधिक ऋण लेने वाला राज्य है। आंकड़ों को देखा जाए तो गहलोत सरकार के राज में करीब दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ गया। पांच वर्षों में वित्तीय प्रबंधन के नाम पर राजस्थान पर ऋण का भार 4 लाख 57 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 6 लाख 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसने राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को ऋणजाल फंसा दिया है।

रिजर्व बैंक ने 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गहलोत सरकार के आर्थिक प्रबंधन तथा सब्सिडी कल्चर को गंभीर बताते हुए चिंता से अवगत कराया। उसकी अनदेखी करने का दुष्परिणाम ये रहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के सिर पर औसतन 71 हजार रुपये का ऋण हो गया है जो कि वर्ष 2017 में 36,880 रुपये था। इसके प्रमुख कारणों में जहां राज्य की जनता को 500 रुपये में सस्ता सिलेंडर देने के लिए 3720 करोड़ रुपये, 50 यूनिट निःशुल्क विद्युत देने के लिए 595 करोड़ रुपये तथा निःशुल्क स्मार्टफोन के लिए 3700 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे थे। लोकलुभावन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण के अलावा कोई साधन नहीं था।

राजकोष को ही गिरवी रख ले लिया ऋण

गहलोत सरकार के कारनामों ने राज्य को जाल में फंसा दिया। वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा देखिए कि राज्य की वर्तमान 186 अरब डॉलर की जीडीपी पर लगभग 76 अरब डॉलर का ऋण हो चुका है। कैग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया कि कैसे गहलोत सरकार ने अपने राजकोष को गिरवी रखकर ऋण लेने का कारनामा कर दिया।

इसके अलावा राज्य के पीएसयू- बोर्डों तथा

कॉरपोरेशन पर लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की पेंडेंसी लेकर आए। इस ऋण के एवज में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक ब्याज के रूप में चुका रहे हैं।

बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने में विफल रहे गहलोत

कैग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गहलोत सरकार की कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ते राजकोषीय घाटे पर भी उंगली उठाई थी। इसमें आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहा गया था कि गहलोत सरकार को नियमानुसार राज्य का राजकोषीय घाटा 3% की सीमा तक बनाए रखना था, किन्तु उस समय राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.61% की सीमा तक पहुंच गया। गहलोत सरकार घाटे को निर्धारित सीमा तक रखने में पूरी तरह विफल रही। जबकि इस कार्यकाल के मध्य में केंद्र सरकार ने कोरोना काल के कारण राज्य सरकारों को राजकोषीय घाटे की सीमा को लेकर विशेष छूट दी थी।

आरबीआई द्वारा उठाई आपत्तियों की अनदेखी

देश के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक आरबीआई ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से गहलोत सरकार को समय-समय पर राज्य के वित्तीय संकट के बारे में चेताया था। अपनी रिपोर्ट में भारी ऋणों के बोझ तले दबे राजस्थान की वित्तीय स्थिति तथा ऋण प्रबंधन पर चिंता व्यक्त की थी। गहलोत सरकार को कई बार चेताया था कि सरकार ने समय रहते राज्य के व्यय तथा ऋण का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया तो राज्य को आने वाले समय में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कैग ने आवश्यकता से अधिक सब्सिडी के भार को भी कम करने की सरकार को सलाह दी थी। इसमें गहलोत सरकार को प्रमुख रूप से निःशुल्क बिजली, महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल बांटना तथा सहकारी बैंकों से किसानों की ऋणमुक्ति की घोषणाओं पर उंगली उठाई थी।

अधिकारियों की कर्ज नीति पर भी आरबीआई ने था चेताया

गहलोत सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आरबीआई में कैश बैलेंस पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने हेतु अग्रिम रूप से 1,01,386 करोड़ रुपये का विशेष वेज एंड मींस लेना पड़ा। इसके लिए आरबीआई को सरकारी खजाने से 112 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। इसके बाद आरबीआई ने राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता पर प्रश्न उठाते हुए एक पत्र लिखा। इसमें कहा कि राज्य अपनी वित्तीय क्षमता से ऊपर जाकर प्रत्येक तिमाही कर्ज ले रहा है।

राजकोषीय आंकड़ों में की जमकर मनमानी

किसी राज्य की ब्यूरोक्रेसी किस सीमा तक वित्तीय अनियमितता कर सकती है। इसका उदाहरण राजस्थान पर कैग की वार्षिक रिपोर्ट में देखने को मिलता है। वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ग्रांट की राशि को गलत ढंग से राज्य के कैपिटल एक्सपेंडेचर हेड में दिखा दिया गया। आंकड़ों में हेरा-फेरी का यह विषय अधिकारियों की मंशा और उनकी कार्य क्षमता पर उंगली उठाता है। बता दें वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त विभाग की ओर से राजस्थान की स्वायत्त संस्थाओं तथा सार्वजनिक कंपनियों के खाते में ग्रांट के रूप में 493 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। उस राशि को पूंजीगत व्यय हेड के रूप में प्रस्तुत किया गया।

कर्मचारियों के फंड का पैसा निशुल्क योजनाओं पर उड़ा दिया

अशोक गहलोत सरकार अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में विभागीय घपलों-घोटालों में घिरी रही। चाहे वह जीपीएफ घोटाला हो, एनपीएस घोटाला हो अथवा आरडब्लूएसएससी घोटाला। वित्त

गहलोत सरकार में एक बिल का कई बार किया गया भुगतान

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के दुरुपयोग पर कैग ने वित्तीय प्रबंधन में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इसमें कई ऐसे कार्य हैं जिनके बिल का भुगतान गहलोत सरकार में कई बार किया गया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्यों से जुड़े बिलों का कई बार बिलों का भुगतान किया गया है।

1 राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत प्रदान की गई अग्रिम धनराशि का दोहरा भुगतान कर दिया गया।

2 नीमराणा नगरपालिका के इनवायस में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर जीएसटी जमा न कराने के कारण राज्य को लगभग 15 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

3 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के चलते 54 लाख से अधिक के विद्युत बिलों का दोहरा भुगतान किया गया।

4 मरणोपरांत मिलने वाली पेंशन का भी दोहरा भुगतान कर दिया गया।

5 एफवीसी बिलों का भी दोहरा भुगतान कर दिया।

6 ठेके पर रखे गए वाहन चालकों को भी दोहरा भुगतान किया गया।

7 पंचायती राज/ निकायों के पीडी फर्म कर फर्म को 5.6 लाख के दोहरे भुगतान कर दिए गए।

8 राज्यकर्मियों के मासिक वेतन/ बकाया वेतन/एरियर/पेंशन का दोहरा भुगतान कर दिया गया।

9 राज्यकर्मियों के मंहगाई भत्ते तथा एचआरए का भी अधिक भुगतान किया गया।

10 इनके अतिरिक्त कई अन्य विभागों में वित्तीय अनियमितताओं पर कैग द्वारा आपत्तियां उठाई गई हैं।

विभाग के अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए जहां राज्य कर्मियों के एनपीएस फंड के पैसे निकालकर निःशुल्क योजनाओं पर उड़ा दिए। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से पूर्व जनवरी-मार्च 2022 में कर्मियों के खातों से कटौती की गई थी। वहीं, कोरोना काल में कर्मियों के वेतन से अंशदान की राशि भी केंद्र सरकार के एनएसडीएल खाते में भी जमा नहीं कराई गई।

इसके अलावा जीपीएफ के सेटलमेंट फंड में जमा तीन हजार करोड़ की धनराशि कर्मचारी कल्याण कोष में जमा करानी थी। उस राशि को भी अधिकारियों ने राजस्व घाटे को कम करने में समायोजित कर दिया गया। जबकि ऐसा करने को लेकर कैग ने आधिकारिक रूप से मना किया था, किंतु अधिकारियों ने हर बार गलत तथ्यों का सहारा लेना बंद नहीं किया।

आरडब्लूएसएससी घोटाले में भी वित्त विभाग ने पेयजल परियोजना आरडब्लूएसएससी में यूजर चार्जेस की राशि को नियम विरुद्ध सीधे पीडी खातों में हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी। जबकि इसके लिए विधानसभा से अनुमति लेना आवश्यक प्रक्रिया है। गहलोत सरकार के इन्हीं मनमाने आचरण के कारण यह मामला न सिर्फ विधायिका के विशेषाधिकार हनन के दायरे में आ गया, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध भी चला गया। इस विषय में कैग द्वारा वित्त विभाग से स्पष्टीकरण देने को संबंधित अधिकारियों को तीन बार पत्र लिखे गए। लेकिन अधिकारियों ने एक भी पत्र का उत्तर देना उचित नहीं समझा।

विद्युत कंपनियों तथा खनन माफियाओं के साथ अधिकारियों ने किए घपले

कैग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राज्य के खनन विभाग तथा विद्युत विभाग के वित्तीय प्रबंधन पर कई प्रश्न उठाए हैं। कैग ने कहा कि भाजपा सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2016-17 में उदय योजना के तहत लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का घाटा कम किया गया था। लेकिन गहलोत सरकार बनने के बाद इसको और कम करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इसका दुष्परिणाम ये रहा कि आज भी राज्य की विद्युत कंपनियों का घाटा कम नहीं हो पा रहा। विद्युत कंपनियों में भारी वित्तीय अनियमितताओं की ओर संस्था ने ध्यान दिलाया है। इसी प्रकार खनन विभाग के अधिकारियों ने खनन माफियाओं के साथ मिलकर विभाग को भारी राजस्व हानि पहुंचाई है। खनन ठेकेदारों के साथ मिलकर किए घपलों का दुष्परिणाम देखिए कि माइनिंग की जो रॉयल्टी विभाग को राजस्व के रूप में प्राप्त होती है वह भी प्राप्त नहीं हुई। ■

जागरूक प्लस मैगजीन

के नवीन संस्करण के

प्रकाशन

की हार्दिक बधाई एवं

शुभकामनाएं

श्री विजय सिंह भारतीय

प्रदेश अध्यक्ष
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भरतपुर
राजस्थान

एड.कविश्वर कान्त भारतीय

जिला अध्यक्ष
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भरतपुर
राजस्थान

राजस्थान की तस्वीर बदल देंगी भजनलाल सरकार की 10 योजनाएं

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

प्रदेश की नींव को मजबूत करने और विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखकर काम किया जा रहा है

भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही विकास के मुद्दे को सर्वोपरि रखा है। सत्ता हस्तांतरण के साथ ही राजस्थान की जनता ने जो-जो सपने संजोये थे, भजनलाल सरकार उन पर खरी उतरती नजर आ रही है। प्रदेशवासियों के लिए ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे लोग आत्मनिर्भर बनें। इसके अलावा किसानों और बुजुर्गों को अधिक से अधिक संबल मिल सके। प्रदेश की नींव को मजबूत करने और विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखकर काम किया जा रहा है। भजनलाल सरकार दिखावटी और रेवड़ी योजनाओं के बजाए भविष्य के राजस्थान के लिए काम कर रही है। राजस्थान में ऐसी 10 योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया गया है जो कि प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल देंगी।

किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। इस योजना को और प्रभावी बनाते हुए भजनलाल शर्मा ने इस राशि को 6000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया है, जो अब चार किस्तों में दी जा रही है। किसान सम्मान निधि को राजस्थान में 12 हजार रुपये तक करने की योजना है। इसकी घोषणा राजस्थान में सरकार बनने से पहले संकल्प पत्र में की गई थी। सत्ता संभालने के साथ ही इस बात पर अमल करते हुए सीएम भजनलाल ने राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार पर 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

गेहूं की फसल पर अतिरिक्त बोनस

प्रदेशवासियों से भाजपा की ओर से संकल्प पत्र में किए गए एक-एक वादे को सीएम भजनलाल पूरा कर रहे हैं। इसके लिए किसानों से जुड़ी एक-एक योजना में सुधार किया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को गेहूं की फसल के बिक्री पर अतिरिक्त बोनस देने का वादा किया था। भाजपा सरकार आने के बाद सीएम ने इस योजना के तहत 125 रुपये अतिरिक्त बोनस देने के वादे को पूरा किया है। एमएसपी के तहत गेहूं बिक्री का मूल्य 2275 रुपये प्रति कुंतल था, जिसको बढ़ाते हुए अब 2400 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। इस योजना के तहत 250 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य सरकार अपने वित्तीय बजट से पूरा करेगी। इतना ही नहीं सीएम भजनलाल ने एमएसपी की राशि को और बढ़ाते हुए 2700 करने का आश्वासन दिया है। सीएम ने सरकार बनने के बाद साफ कर दिया है कि संकल्प पत्र में किए गए वादों को किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा।

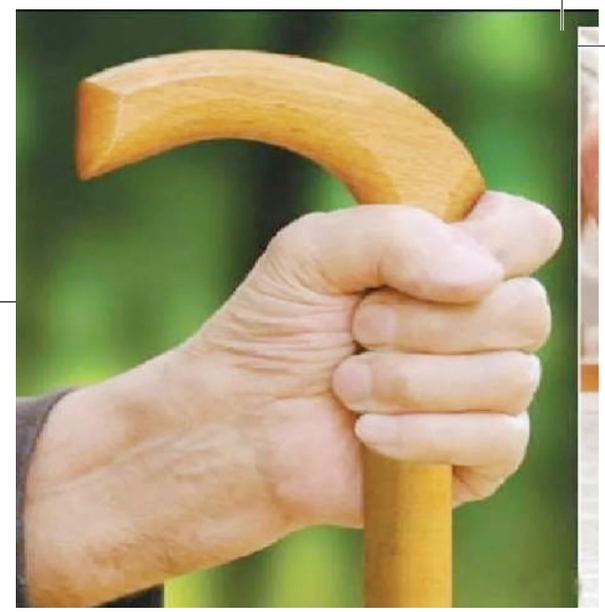

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी

प्रदेश में भजनलाल सरकार आने के बाद से जनता के विकास के लिए समय-समय पर योजनाओं में सुधार और नई योजनाओं को अलग तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह की राशि से बढ़ाकर 1150 रुपये प्रति माह कर दिया है। भजनलाल सरकार की योजना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह तक किया जाए। इससे राज्य सरकार पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मां वाउचर योजना के तहत मुफ्त सोनोग्राफी

भजनलाल सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा है। सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब सभी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में सोनोग्राफी हो सकेगी। भजनलाल सरकार ने 'मां वाउचर योजना' के तहत इसकी शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब यह सुविधा पूरे राजस्थान में उपलब्ध होगी। इस योजना से सरकारी और कुछ निजी केंद्रों पर भी मुफ्त सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी। इस योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक की गर्भवती महिलाएं उठा सकेंगी।

इस योजना का लाभ लेने हेतु 'गर्भवती महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड आधारित एक ई-वाउचर मिलेगा। इसे देकर किसी भी सूचीबद्ध निजी केंद्र में निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। वाउचर की वैधता 30 दिन की होती है। अगर इस बीच महिला समय पर सोनोग्राफी नहीं करवाती है, तो वह दोबारा चिकित्सा केंद्र जाकर वाउचर की समय सीमा 30 दिन और बढ़वा सकती है। यह सुविधा सिर्फ एक बार के लिए ही मान्य है।

ईआरसीपी से खत्म होगा पूर्वी राजस्थान में जलसंकट

ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतारने के लिए भजनलाल शर्मा की सरकार ने बड़ा कार्य किया है। भजनलाल सरकार ने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के पूरी तरह से धरातल पर उतरने के बाद 21 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। इस परियोजना के तहत कालीसिंध, पार्वती और मेज नदी के व्यर्थ बहने वाले मानसून के पानी का

■ भाजपा की ओर से संकल्प पत्र में किए गए एक-एक वादे को सीएम भजनलाल पूरा कर रहे हैं

■ लखपति दीदी योजना का लक्ष्य पांच साल के भीतर प्रदेश की 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना के ऊपर करीब 44 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 40 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी।

इस संबंध में सीएम भजनलाल ने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस योजना की शुरुआत की और हमने इसे आगे बढ़ाया है। आलू से सोना तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसान को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए, तो वह मिट्टी से सोना जरूर उगा सकता है। भाजपा सरकार ने इस योजना को मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस ने पिछले पांच साल इस मामले पर केवल राजनीति की'। ईआरसीपी को लेकर एक भी पत्र संबंधित मंत्रालय को नहीं लिखा। वहीं, केंद्र की ओर से बैठक में बुलाए जाने के बाद भी ना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और ना ही संबंधित विभाग के मंत्री बैठक में शामिल हुए। कभी भी इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास नहीं किया।

प्रदेश में पांच लाख घरों की छत पर लगेगा सोलर पैनल

भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में ही प्रदेश के पांच लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने के का संकल्प किया है। इसके साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है क्योंकि प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति और बिजली कंपनियों पर बढ़ते कर्ज को देखकर भजनलाल सरकार सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा में इस ऐलान के बाद जनता में खुशी की लहर है। राजस्थान में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई। प्रदेश के पांच लाख घरों में सोलर पैनल लगने से हर साल करीब 255 करोड़ यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना का लाभ फिलहाल डेढ़ लाख आय या उससे कम वार्षिक आय वाले लोगों को मिलेगा।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से लगभग एक करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जो कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे बनने वाली बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी।

पांच साल में 15 लाख दीदी बनेंगी लखपति

राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ही महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पांच साल के भीतर प्रदेश की 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सिर्फ 2.5 फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 40,000 नए स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया जाएगा। इसमें 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सशक्त हो सकेंगी।

सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। इस तरह भजनलाल सरकार ने महिलाओं को समाज में बराबरी का मौका देने के लिए कई कार्य किए हैं,

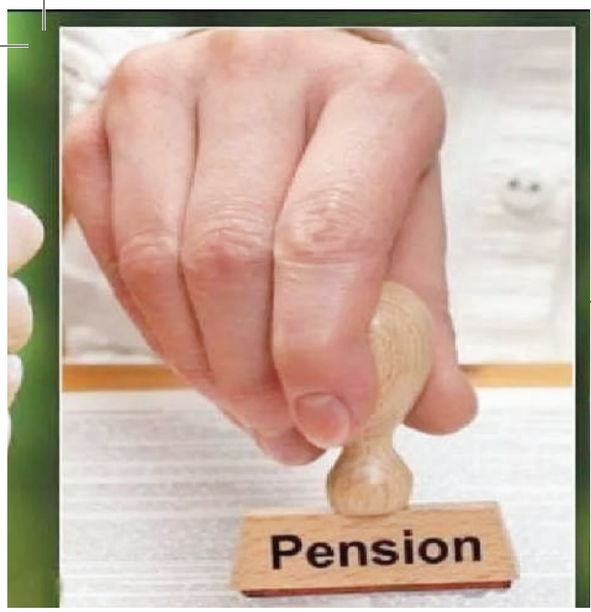

जिसकी जनता खूब सराहना कर रही है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लखपति दीदी माना गया है, जिनकी सालाना आय घर में रहकर काम करते हुए कम से कम एक लाख है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज

भजनलाल सरकार की एक और काफी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। केंद्र की मोदी सरकार एक योजना लेकर आई आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत गरीब लोगों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। भजनलाल सरकार ने इस योजना को और अधिक अपग्रेड किया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना तहत गरीब लोगों का इलाज मुफ्त है। इसके अलावा दुर्घटना बीमा के तौर पर 10 लाख रुपये तक का प्रावधान है। योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का इलाज निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। ये निःशुल्क सेवा गरीब लोगों के लिए हैं। इसके अलावा अन्य लोग 850 रुपये महीना जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की इस योजना से गरीब लोग भी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा पा रहे हैं।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल से नल

राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन योजना को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया है। भजनलाल सरकार की कोशिश है कि राजस्थान के हर घर नल से जल पहुंच सके। इसके लिए गांवों में पानी की टंकी बनवाई जा रही हैं। इसके अलावा गांवों में पानी की लाइन डाली जा रही हैं। भजनलाल सरकार ने इसी माह नवंबर 2024 में जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए 658 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पूर्व की सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से कार्य पूरे नहीं हो सके। अब भाजपा सरकार हर घर जल से नल पहुंचाने के लिए दृढ़संकल्पित है।

केंद्र सरकार की योजना में गहलोत सरकार के समय भारी गड़बड़ी की गई। इसके बावजूद घरों तक नल से जल नहीं पहुंच सका। भजनलाल सरकार में जल जीवन मिशन से जुड़ी अनियमितताओं को दूर कर जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रदेशवासियों

आलू से सोना तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसान को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए, तो वह मिट्टी से सोना जरूर उगा सकता है।

- भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

को जल्द हर घर में नल से जल मिल सकेगा।

राजस्थान जल जीवन मिशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए जिले के ब्लॉक या प्रखंड कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। भजनलाल सरकार अब तक 46.31 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 92.84 लाख ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

राजस्थान पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 20 हजारों युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित

राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी काम कर रही है। राजस्थान में अनगिनत ऐसी धरोहर हैं, जिसे देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोग आते हैं। ऐसे में सरकार इन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के भी अवसर पैदा कर रही है। इसको लेकर भाजपा सरकार ने पर्यटन संवर्धन योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही पर्यटन स्थलों को और आकर्षक बनाया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर कहा कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों और मेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए विशेष मार्केटिंग रणनीति बनाई जा रही है। वहीं, पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अगले दो वर्षों में प्रदेश के 20 हजार युवाओं और लोक कलाकारों को पारंपरिक कला में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह उनके लिए रोजगार सृजन के साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में मदद करेगा। ■

जागरूक प्लस मैगजीन

के नवीन संस्करण के

प्रकाशन

की बधाई एवं

शुभकामनायें

देवेन्द्र चामड

devendrachamadbharatpur @officialdevendrachamad @Devendrachamad

अध्यक्ष : ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया एसोसियेशन, भरतपुर

जादूगर कौन...? सीएम भजनलाल या गहलोत

राजस्थान वन न्यूज नेटवर्क

राजस्थान में हुए उपचुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परंपरा बदल दी है। उपचुनावों में अक्सर होने वाली भाजपा की हार की परंपरा को बदलते हुए उन्होंने इतिहास रच दिया। उपचुनाव में भाजपा के दिग्गज सीएम जो अब तक नहीं कर सके वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर दिखाया है। सीएम भजनलाल शर्मा का उपचुनावों में सक्सेस रेट पूर्व सीएम अशोक गहलोत से भी बेहतर है, जबकि उन्हें सीएम बने सिर्फ 11 महीने हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का उपचुनावों में सक्सेस रेट 72 फीसदी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि असली जादूगर कौन...? सीएम भजनलाल या अशोक गहलोत।

भजनलाल शर्मा की अगुवाई में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ पांच सीटें जीती हैं। यहां तक कि वर्ष 2000 में छह सीटों पर हुए उपचुनावों में भी भाजपा ने सिर्फ चार सीटें जीतीं थीं। वर्ष 1952 के प्रथम विधानसभा उपचुनाव से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक कुल 106 सीटों के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। वहीं, भाजपा के गठन के बाद 1980 में होने के पश्चात अब तक 61 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जैसा प्रदर्शन भाजपा ने उपचुनावों में किया है, ऐसा कीर्तिमान कोई नहीं रच सका।

राजस्थान में 2013 से 2024 के बीच 16 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस दौरान 2018 तक भाजपा सत्ता में थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा महज 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। इनमें से आठ सीटों पर तब उपचुनाव हुए जब भाजपा की सरकार थी। इसके

10 साल में जो भाजपा नहीं कर सकी, वह एक साल में किया

21 साल बाद कांग्रेस को झुंझनू में हार का स्वाद चखाया है

उपचुनावों में भाजपा की भारी जीत को लेकर साफ संकेत हैं कि जनता भजनलाल शर्मा की सादगी को पसंद कर रही है

बावजूद कांग्रेस ने पांच सीटें जीती थीं और भाजपा महज दो सीट जीत पाई थी।

वोटिंग प्रतिशत कम होने के बावजूद रचा इतिहास

राजस्थान में जब भी वोटिंग प्रतिशत गिरता है तो माना जाता है कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा। विधानसभा चुनाव 2023 के मुकाबले सात में से छह सीटों पर उपचुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा था। ऐसे में राजनैतिक पंडितों का आंकलन था कि कांग्रेस को फायदा होगा और भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2013 के बाद मतदान प्रतिशत गिरने पर कांग्रेस ने नौ सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा सिर्फ चीन सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार उपचुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम होने के बावजूद सीएम भजनलाल शर्मा ने इतिहास रचा। विधानसभा चुनाव 2023 के मुकाबले उपचुनाव में सात में से जिन छह सीटों पर मतदान प्रतिशत गिरा है, उनमें से भाजपा ने चार सीटें जीती हैं। इनमें झुंझुनू, सलूंबर, देवली-उनियारा और रामगढ़ की सीट शामिल है। वहीं, कांग्रेस इनमें से सिर्फ एक सीट दौसा की ही जीत सकी है, जहां पर वोटिंग प्रतिशत गिरा था।

झुंझुनू में 21 वर्ष पश्चात ढहाया कांग्रेस का किला

झुंझुनू विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में 21 वर्ष पश्चात भाजपा ने विजय प्राप्त कर कांग्रेस का मजबूत किला ढहा दिया। भाजपा के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट पर अमित ओला को 42 हजार के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया है। इससे पहले राजेंद्र भांबू को लगातार दो बार इसी सीट से अपने भाग्य को आजमाने में हार का सामना करना पड़ा था। जबकि विधायक से सांसद बने बृजेंद्र सिंह ओला चार बार से इस सीट से विधायक थे। इस हार को बृजेंद्र सिंह ओला तथा कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि झुंझुनू की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। इस क्षेत्र पर अमित ओला के बाबा और कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला का प्रभाव रहा है। लेकिन कांग्रेस की यह परंपरागत सीट भी सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने छीन ली है।

आरएलपी के गढ़ में घुसकर किया सफाया

उपचुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधानसभा में सफाया कर दिया। उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल की पराजय के साथ ही राजस्थान विधानसभा में आरएलपी के विधायकों की संख्या शून्य हो गई है। यहां से भाजपा के रेवंतराम डांगा ने कनिका बेनीवाल को अप्रत्याशित ढंग से 13,901 मतों से हरा दिया है। जहां रेवंतराम को 1,08,628 मत प्राप्त हुए तो कनिका को 94,727 मत मिले। सबसे चौंकाने वाला परिणाम इस सीट से कांग्रेस को लेकर दिखा। यहां पर कांग्रेस की जमानत तक नहीं बचा सकी और मात्र 5454 मत मिले।

बता दें खींवसर विधानसभा सीट पर 2008 में प्रथम चुनाव हुआ था। तब से लेकर अब तक आरएलपी प्रमुख और वर्तमान में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के परिवार का ही कब्जा रहा। इस विधानसभा चुनाव में बेनीवाल के इस अभेद्य किले को भी भाजपा और सीएम भजनलाल शर्मा ने भेद दिया।

उपचुनावों में कमजोर प्रदर्शन के मिथक को तोड़ा

अपने 11 महीने के कार्यकाल के बीच उपचुनावों की प्रथम परीक्षा में सीएम भजनलाल पूरी तरह से खरे उतरे हैं। सात सीटों पर हुए उपचुनावों में अपने माइक्रो मैनेजमेंट के बल पर पांच सीटें जिताकर राजनीतिक पंडितों को हक्का-बक्का कर दिया है। वह भी तब जब पिछले वर्ष 2023 में विधानसभा चुनावों में भाजपा को इन जीती हुई पांच सीटों में से चार पर हार का सामना करना पड़ा था। इन चार सीटों में खींवसर जैसी सीट भी शामिल है। भाजपा ने खींवसर विधानसभा सीट को जीतकर हनुमान बेनीवाल के अभेद्य किले को ही ढहा दिया है।

माइक्रो मैनेजमेंट से सभी को चौंकाया

सीएम भजनलाल शर्मा ने उपचुनावों में कांग्रेस से जीती सीटों को छीनकर पार्टी को अपने सटीक माइक्रो मैनेजमेंट से सभी राजनीतिक दिग्गजों को चौंका दिया। इस उपचुनाव में जिन सात सीटों खींवसर, देवली-उनियारा, रामगढ़, झुंझुनू, सलंबूर, दौसा तथा चौरासी पर मतदान हुआ, उनमें केवल सलंबूर सीट ही भाजपा के पास थी। जबकि खींवसर, झुंझुनू, रामगढ़ तथा देवली-उनियारा सीटों को भाजपा ने छीन लिया है। भजनलाल शर्मा इस तरह बनें माइक्रो मैनेजमेंट गुरु..

- भजनलाल शर्मा ने चुनाव का सारा दायित्व अपने ऊपर लेकर सबसे पहले टिकट वितरण में दावेदारों के जीतने की संभावना, स्थानीय कार्यकर्ताओं की पसंद तथा संगठन में कार्य करने वालों दावेदारों को प्राथमिकता दी।
- निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहे बागियों को चुनाव में उतरने से रोकने में सफल रहे।
- बूथ स्तर तक निगरानी रखने के साथ ही भजनलाल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दीपोत्सव के दिन भी चुनावी क्षेत्रों में रोके रखा। सामाजिक समीकरणों को साधने तथा कमजोरियों पर काम करने का उत्तरदायित्व सौंपा।
- सभी प्रत्याशियों के नामांकन में स्वयं उपस्थित रहकर जनसभाओं को संबोधित कर मतदाताओं को विश्वास दिलाया।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मंत्रियों तथा संगठन के महत्वपूर्ण नेताओं की संयुक्त टीमों को चुनाव मैनेजमेंट में उतारा।
- संगठन में काम करने के अपने अनुभव का भरपूर उपयोग किया। प्रत्येक विधानसभा सीट पर सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें करवाईं। स्वयं 44 सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कीं और 14 जनसभाओं को संबोधित किया।
- सभी सात सीटों की मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व अपने पास रखा।
- महाराष्ट्र चुनावों में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ मिलकर शानदार समन्वय स्थापित रखा।
- बूथ कार्यकर्ताओं, मंडल कार्यकर्ताओं, शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं, विधानसभा चुनाव संचालन समितियों, प्रदेश के पदाधिकारियों, प्रचार अभियान में लगे कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न व्यवस्थाओं में लगी टीमों के साथ निरंतर फोन से संपर्क बनाए रखा।

पहली ही परीक्षा में जादूगर बनकर उभरे भजनलाल

कभी राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के अशोक गहलोत को जादूगर की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन इन उपचुनावों में भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाने के पश्चात सीएम भजनलाल को राजनीति का नया जादूगर कहा जा रहा है। उपचुनावों में अशोक गहलोत कहीं नजर नहीं आए जबकि सीएम भजनलाल शर्मा छाए रहे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जादूगर कौन? सीएम भजनलाल शर्मा या पूर्व सीएम अशोक गहलोत? उपचुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के पश्चात भजनलाल शर्मा पहले से कई गुना मजबूत हो गए हैं। अपने निर्णयों को लेकर राजस्थान के सबसे संवेदनशील सीएम के रूप में उभरे हैं। जनता ने उनके निर्णयों पर इन परिणामों के माध्यम से मुहर लगा दी है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने इन चुनावों का उत्तरदायित्व पूरी तरह अपने कंधों पर लेकर अपनी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो चुनाव परिणाम आते ही इस विजय का सारा श्रेय सीएम भजनलाल को दे दिया। पार्टी के अन्य नेता भी उनकी नेतृत्व क्षमता की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं।

भजनलाल शर्मा में बढ़ा शीर्ष नेतृत्व का भरोसा

उपचुनावों में शानदार जीत के बाद सीएम भजनलाल का कद अब पार्टी में और बढ़ गया है । जिसका प्रभाव पार्टी के बड़े निर्णयों में देखने को मिल सकता है। राजनैतिक पंडित मान रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का विश्वास शुरू से ही भजनलाल शर्मा में रहा है। लेकिन उपचुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन से सीएम भजनलाल में भरोसा और बढ़ गया है। उनको अब और फ्री हैंड दिया जा सकता, जिससे भविष्य में मंत्रिमंडल को लेकर अपनी इच्छानुसार फैसले ले सकेंगे। इसके अलावा राजनैतिक महत्वाकाक्षांओं को लेकर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर विराम लगेगा।

भजनलाल शर्मा की सादगी को पसंद कर रही जनता

सीएम भजनलाल शर्मा की सादगी को राज्य की जनता द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। उनके करीबी लोगों और नेताओं ने बताया कि भजनलाल शर्मा की दिनचर्या बहुत ही आम है। जनता से जुड़े विषयों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनके निराकरण हेतु यथोचित कदम उठाने में भी विलंब नहीं करते हैं। वह कभी आमजनों को ऐसा महसूस नहीं होने देते जैसे कि उनसे पहली बार मिल रहे हैं। सीएम बनने के पश्चात उनका भरी सभा में अपने गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लेना जनता के दिलों में घर कर गया। इसके जरिए दर्शाया कि सीएम बनने के पश्चात भी उन्होंने सनातनी नैतिक मूल्यों को नहीं त्यागा है। विनम्रता को उन्होंने शोभा के रूप में धारण कर रखा है। ■

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट की ऐतिहासिक सफलता के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को बहुत-बहुत बधाई।

- इतिहास रचते हुए भजनलाल सरकार ने 27 लाख करोड़ से अधिक निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए
- प्रदेश के 5 लाख युवाओं को मिलेगा निजी क्षेत्र में रोजगार

आभार

नवीन पाराशर

सदस्य सलाहकार समिति नागरिक उड्डयन मंत्रालय

(विधानसभा अलवर)

राजस्थान वन करंट अफेयर्स

राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय

●राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जाएगा।
●राजस्थान का पहला आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित है।

घरेलू गैस सिलेंडर अब 450 रुपये में

● प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा 'बीपीएल' श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
●अब राजस्थान में इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूँ प्राप्त करने वाले परिवारों के लाभान्वितों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा।

माँ वाउचर योजना का शुभारम्भ

● शुभारम्भः 8 अगस्त, 2024
●मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने के लिए 'माँ वाउचर योजना' का सम्पूर्ण प्रदेश में शुभारम्भ किया।
●योजना की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के तीन जिलों- बारां, भरतपुर और फलौदी में 8 मार्च, 2024 को की गई थी।
●इस योजना को अब सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
●लाभः इस योजना के माध्यम से राजकीय सोनोग्राफी केन्द्रों के साथ-साथ निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर भी निशुल्क सोनोग्राफी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
●माँ वाउचर योजना के तहत् गर्भवती महिला की दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भकाल के दौरान की एक सोनोग्राफी निःशुल्क कराई जाएगी।

मोहनपुरा- फरकिया, अजमेर

●हाल ही में मोहनपुरा- फरकिया, अजमेर में तांबें के भंडार मिले हैं।

अरण्यम पुस्तक के लेखक

● राहुल भटनागर

लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत

● राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हो चुकी है।
●घोषणा- 8 फरवरी, 2024 (लेखानुदान, 2024-25)
●उद्देश्य- बालिकाओं को शुरुआत से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्रदान करना ।
●बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को समाप्त कर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना ।
●गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर 1,00,000 रुपये लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा।

फल-फूल मंडी

●राजस्थान के बजट 2024-25 घोषणा के अनुसार प्रदेश में फल-फूल मंडी सादड़ी (पाली) में स्थापित की जाएगी।

राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी

●मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ (अजमेर) में किया।
●यह स्कूल फ्लाइट प्रशिक्षण का राज्य

में प्रथम केंद्र है।

भड़ला सोलर पार्क
●अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला, जोधपुर का सैटेलाइट फोटो जारी किया।

अमृता देवी पुरस्कार (वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में)
●अमृता देवी पुरस्कार के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में हाल ही में निम्न व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है-

वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी
●के गजेंद्र सिंह मांझी (2020 के लिए)
●पदम सिंह राठौड़ (2021 के लिए)
●मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा (2022 के लिए)

वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी
●श्याम सुंदर पालीवाल (2020 के लिए)
●अभिलाषा और बच्चू सिंह वर्मा (2021 के लिए)
●पवन कुमार जैन (2022 के लिए)

कैलाश चंद मीणा
●आरपीएससी के नए कार्यवाहक के पद पर कैलाश चंद मीणा को नियुक्त किया गया है।

75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन
●हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को नवनिर्मित दूदू जिले से 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया।

राजस्थानी तीज महोत्सव
●राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को बीकानेर हाउस, दिल्ली में किया गया।

हरियालो राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम
●शुरुआत- 7 अगस्त (हरियाली तीज पर)।
●शुभारंभ- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा।
●स्थान- एसडीआरएफ कैंपस, गाड़ोता, दूदू (राजस्थान)।
●लक्ष्य- एक दिन में एक करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
●जिला स्तर पर मातृ वन स्थापित करने की घोषणा हुई ।
●इस अभियान में बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, माखन कटोरी, नेती पीपल जैसे पौधे लगाये जाएंगे।
● हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से इन पौधों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का निधन
● 8 अगस्त 2024 को सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, ये भाजपा के राजस्थान से विधायक थे।

ज्ञान संकल्प पोर्टल
●सरकारी स्कूलों को भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल को तैयार किया गया है।

मीरा महोत्सव
●10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी (नागौर) से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया।
●यह 520 वां मीरा महोत्सव था।

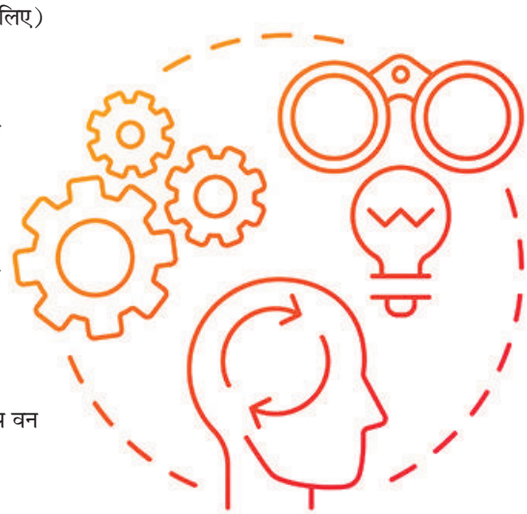

दक्षिणा जोशी
●भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता है ।

ऑपरेशन अलर्ट
●बीएसएफ द्वारा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त तक 2024 तक ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया।

ताइक्वांडो चैंपियनशिप
●बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने स्वर्ण पदक जीता।

पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
●भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (MP-ATGM) हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण जैसलमेर में किया।

राजस्थान की पहली चीता सफारी
●राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी रावतभाटा, गांधीसागर, चित्तोड़गढ़ में बनेगी।

राज्य में नई लेपर्ड सफारी
●काजीपुरा गंगा भैरव घाटी, अजमेर में राज्य की नई लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी।

मिशन मधुहारी
●शुरुआत- 12 अगस्त 2024 से।
●शुभारंभ- स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 12 अगस्त 2024 को शुरुआत की।
●उद्देश्य- टाइप-1 डायबिटीज से बचाव के लिए, गैर संक्रामक रोगों से बचाव हेतु ।
●संचालन- चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित।

राजीव गांधी लाइफटाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024
●तापोश चटर्जी (क्रिकेटर) को राजीव गांधी लाइफटाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 दिया गया।

राजस्थान में पहला किसान कॉल सेंटर शुरु
●जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू हो चुका है।
●टोल फ्री नंबर- 1800-180-3000

मित्र शक्ति युद्धाभ्यास
●भारत और श्रीलंका के मध्य
●स्थान- श्रीलंका में
●संस्करण- 10वां
●आयोजन- 12 से 25 अगस्त 2024 तक।
●इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की ओर से राजपूताना राइफल्स की उदयपुर बटालियन ने भाग लिया।

फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024
●जयपुर की वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का ख़िताब जीता।

दुर्गादास राठौड़ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड
●जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386 वीं जयंती समारोह में मांड गायिका गवरी देवी को दुर्गादास राठौड़ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024
●श्रीलंका में हुई अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की दीपा माथुर ने महिला युगल में स्वर्ण

पदक और मिक्स युगल में रजत पदक जीता।

सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024

●जैसलमेर जिले के निवासी अशोक चारण को नई दिल्ली में सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।

वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप 2024

●वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप (इंदौर) में राजस्थान की अक्षिता डागर और जूही प्रजापति ने क्रमशः रजत पदक व कांस्य पदक जीता।

अटल भूजल योजना रिपोर्ट 2024

●अटल भूजल योजना में अब राजस्थान प्रदेश सातवें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना

●शुरुआत- 22 अगस्त 2024 से
●राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुपालन में राज्य में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना' लागू की गई है।
●उद्देश्यः राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है।
●योजना का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा।

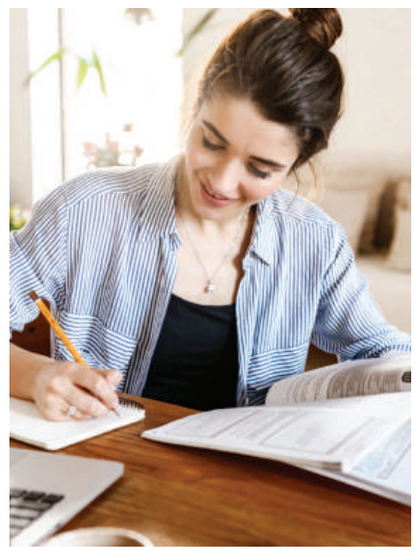

●प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में राज्य के निकटतम सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार 10,000 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र देगी।

विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट

●उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया।

मानवेंद्र सिंह जसोल

●राजस्थान फुटबाल संघ का अध्यक्ष चुना गया है।

मीता पंडित
●मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान, जोधपुर द्वारा 'मरुधरा गौरव सम्मान 2024' से मीता पंडित को सम्मानित किया गया है।

रवनीत सिंह बिट्टू

●भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित किया गया है।
●राजस्थान से राज्य सभा की एक सीट के लिए सम्पन्न चुनाव में निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने उनके निर्वाचन की घोषणा 27 अगस्त 2024 को की।
●राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के चुने जाने के बाद अब राज्यसभा में राजस्थान से भाजपा और कांग्रेस के 5-5 सदस्य हो गए हैं।

स्टेट रिमोट सब सेंटर

●राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में स्टेट रिमोट सब सेंटर खोलने की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024

●राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर से बलजिंदर सिंह और बीकानेर निवासी हुकम चंद चौधरी का चयन हुआ।
●देश के कुल 50 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल शुरू

●राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारंभ 28 अगस्त 2024 को किया गया।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

●जोधपुर और पाली शहरों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया।

मिसेज राजस्थान 2024

●सलोनी वर्मा को मिसेज राजस्थान 2024 का ख़िताब दिया गया।

आरएफ- 290

●हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर द्वारा तैयार की गई सौंफ की आरएफ- 290 किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ■

एक विश्वसनीय नाम
जिसका डिटर्जेंट पाउडर आलीशान
अब नए फॉर्मूला के साथ

भरतपुर की नंबर वन सर्फ

Bharatpur Live सर्फ

खारे और मीठे पानी में पूरी
तरह से कारगर

डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए
आज ही संपर्क करें

8503829782

बाल्टी और मशीन
वॉश के लिए
सर्वोत्तम